

## अध्याय II : संघ शासित क्षेत्र (व्यय क्षेत्र)

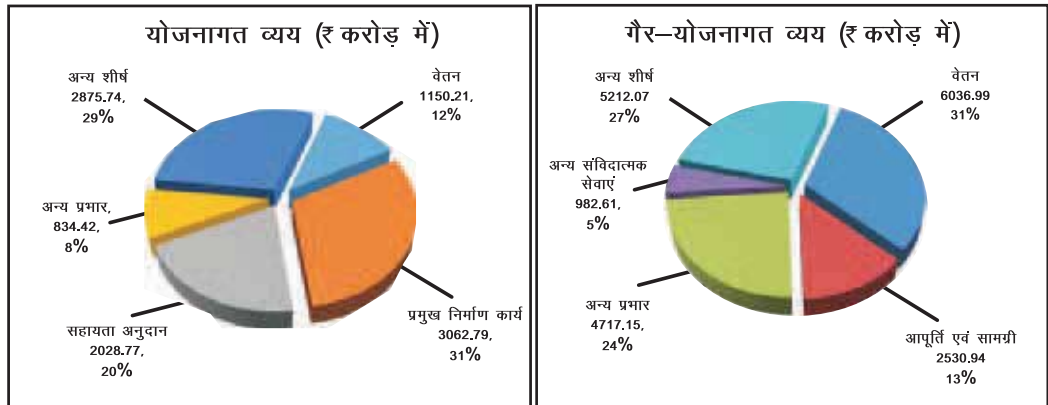
2011-12 से 2013-14 की अवधि हेतु बिना संविधान वाले सं.शा.क्षे. के बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक व्यय के विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान			संशोधित अनुमान			वास्तविक व्यय		
	योजनागत	गैर योजनागत	कुल	योजनागत	गैर योजनागत	कुल	योजनागत	गैर योजनागत	कुल
2011-12	3140.22	6071.69	9211.91	3027.77	6682.68	9710.45	2953.40	6619.62	9573.02
2012-13	4015.20	6688.70	10703.90	3362.76	7057.05	10419.81	3334.70	7046.18	10380.88
2013-14	4483.30	5700.88	10184.18	3757.41	5817.89	9575.30	3663.83	5813.96	9477.79

निम्नलिखित पाई-चार्ट तीन-वर्ष की अवधि के दौरान योजनागत तथा गैर-योजनागत के अंतर्गत किए गए व्यय के प्रमुख घटकों को दर्शाता है:

**चार्ट-1**



जबकि योजनागत शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का 31 प्रतिशत प्रमुख कार्यों पर व्यय किया गया था, जिसके बाद सहायता अनुदान भुगतानों पर 20 प्रतिशत, गैर-योजनागत व्यय का प्रमुख अंश वेतनों पर 31 प्रतिशत का था।

### संघ शासित क्षेत्र अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह

#### 2.1 2011-14 की अवधि हेतु पत्तन प्रबंधन बोर्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में वित्तीय प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण

##### 2.1.1 प्रस्तावना

अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (अ.नि.द्वी.स.) के संघ शासित क्षेत्र की जीवन-रेखा नौपरिवहन है। अ.नि.द्वी.स. में 23 अधिसूचित पत्तन तथा 14 अन्य पत्तन हैं। पत्तन गतिविधियों

पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अक्टूबर 1983 में पत्तन प्रबंधन बोर्ड की स्थापना की गई थी। सचिव, अ.एवं नि. प्रशासन अध्यक्ष है तथा मुख्य पत्तन व्यवस्थापक बोर्ड का कार्यात्मक शीर्ष है।

**प.प्र.बो. के प्राथमिक उद्देश्य हैं:**

- पोत संबंधी सेवाएं तथा मार्गदर्शन, बर्थिंग/अनबर्थिंग जैसी सुविधाएँ प्रदान करना
- यात्रियों तथा कार्गो के लिए हैंडलिंग सुविधाएं तथा कार्गो को छुड़ाने की सुविधा प्रदान करना
- बंदरगाहों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए नियमावली बनाना
- नौपरिवहन तथा सामान के भंडारण तथा अन्य संपत्ति को लाने ले जाने के लिए प्रभारों को तैयार करना
- सुरक्षित बर्थिंग के लिए समुद्री संचार तथा नौवहन सहायता प्रदान करना।

पत्तनों/बंदरगाहों के अनुरक्षण आवश्यकताओं तथा सभी मुख्य निर्माण गतिविधियां अण्डमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य (अ.ल.बं.नि.का.), नौपरिवहन मंत्रालय (नौ.प.मं.) के अंतर्गत एक विभाग द्वारा की जाती हैं।

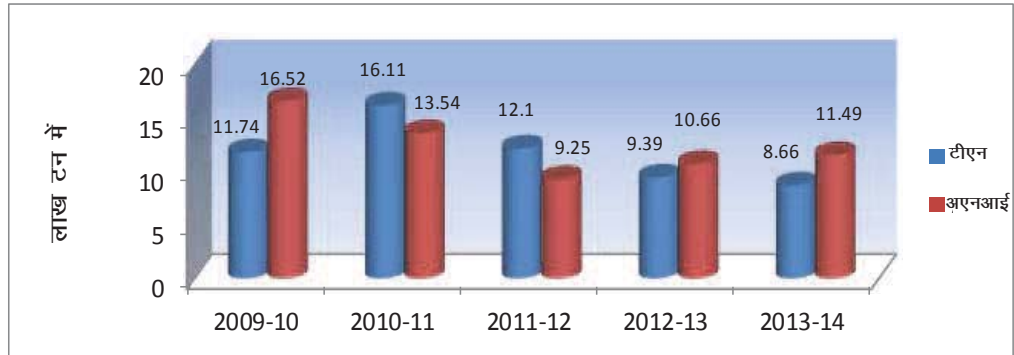
### **2.1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र**

2011-12 से 2013-14 की अवधि को शामिल करते हुए 'प.प्र.बो. का वित्तीय प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण' की लेखापरीक्षा की गई थी।

### **2.1.3 प.प्र.बो. की स्थिति**

अक्टूबर 1983 में अपनी स्थापना के समय पर यह परिकल्पित किया गया था कि मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अंतर्गत मुख्य पत्तनों के न्यासी बोर्ड के समान शक्तियां एवं कार्य पत्तन प्रबंधन बोर्ड के होंगे। परंतु अपने राजस्व में वृद्धि करने एवं अ.नि.द्वी.स. में पत्तनों के विकास संरक्षण और विकास सुनिश्चित करने तक प.प्र.बो. को अपने कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए प.प्र.बो. के राज्य समुद्री बोर्डों के समान ऐसे स्वायत्त स्थिति या शक्तियों को प्रदान नहीं किया था। पिछले 5 वर्षों के दौरान अ.नि.द्वी.स. के पत्तनों पर हैंडल किए गए कार्गो की तुलना दर्शाती है कि प.प्र.बो., तमिलनाडु समुद्री बोर्ड के सममूल्य था जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट-2



प.प्र.बो. प्रशासन के सिविल विभाग के रूप में निरंतर रूप से कार्य कर रहा था। यद्यपि, पो.प्र.बो. का प्राथमिक उद्देश्य पत्तन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रभारों को तैयार करना तथा पत्तनों एवं बंदरगाहों के संरक्षण हेतु नियमावली बनाने के लिए है, परंतु उचित शक्तियों की अनुपस्थिति में, इसके द्वारा ऐसी कोई नियमावली/प्रभारों को तैयार नहीं किया गया था। अ.नि.द्वी.स. के लोगों को सेवाओं एवं सुविधाओं की प्रभावी संवितरण हेतु न तो कोई नियम/नियमावली/मैनुअल को तैयार किया गया था न ही भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अंतर्गत नौ.प.मं. की अधिसूचनाओं के आधार पर जहाज एवं कार्गो संबंधित सेवाओं के लिए कोई प्रभारों का संग्रहण किया गया था।

प.प्र.बो. की वर्तमान की अस्थिर स्थिति के साथ प.प्र.बो. प्रभावी एवं कुशल कार्यान्वयन हेतु नियमों को तैयार करने में प्रशासन की विफलता के कारण विभिन्न कमियां हुई जिसकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है:

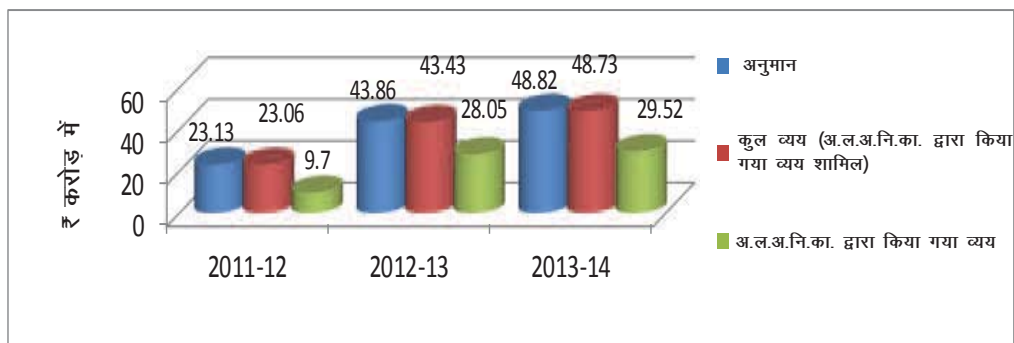
## 2.1.4 वित्त एवं लेखे

### 2.1.4.1 बजट एवं व्यय

गृह मंत्रालय द्वारा आवंटित संघ शासित क्षेत्र (सं.शा.क्षे.) बजट से प.प्र.बो. ने निधियां प्राप्त की थीं। योजनागत (शीर्ष 3051 एवं 5051 के अंतर्गत) तथा गैर-योजनागत निधियों (शीर्ष 3051 के अंतर्गत) के लिए बजट एवं व्यय की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

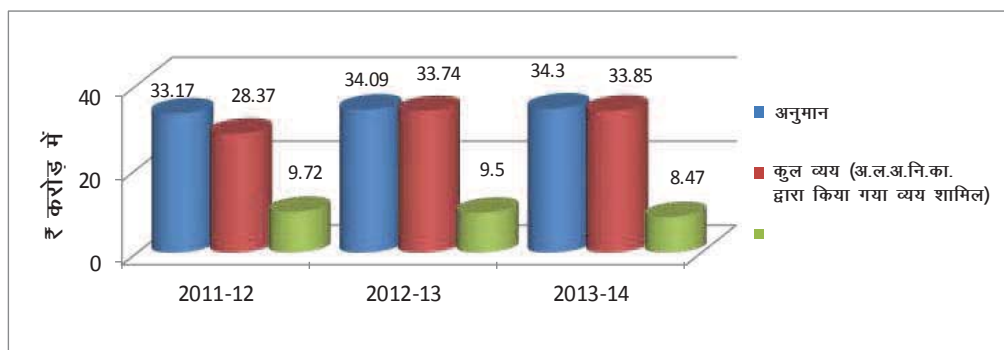
चार्ट-3

योजनागत निधियां



## चार्ट-5

## गैर-योजनागत निधियां



प.प्र.बो. द्वारा किया गया व्यय मुख्य रूप से विमान का संचालन<sup>1</sup>, नौवहन सहायता<sup>2</sup>, जहाज कूली गतिविधियां<sup>3</sup>, मरम्मत/रखरखाव घाटों के निर्माण आदि पर हुआ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प.प्र.बो. वसूल किए गए राजस्व में से किसी प्रकार का व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, जिसे भारत की समेकित निधि में जमा करना था।

यह पाया गया था कि मुख्य निर्माण कार्यों, उपकरण के प्रापण, घाटों का रखरखाव तथा प्राधिकरण पत्र के माध्यम से अ.ल.ब.नि.का. नामक निष्पादन अभिकरण को कार्गो हैंडलिंग उपकरण का स्थानांतरण कर दिया गया था क्योंकि प.प्र.बो. के पास चेक आहरण शक्तियां नहीं थीं। हालांकि, अ.ल.ब.नि.का. से पूर्ण हुई परिसंपत्तियों को लेने की कोई प्रणाली नहीं थी। 2011-14 के दौरान अ.ल.ब.नि. का द्वारा ₹44.14 करोड़ के शुरू किए गए 22 निर्माण कार्यों में से ₹12.20 करोड़ के नौ (9) निर्माण कार्य मार्च 2014 तक पूर्ण हो चुके थे (अनुबंध - 1)। प्रचलित अभ्यास के अनुसार, कोई भी पूर्ण हुए निर्माण कार्य प.प्र.बो. द्वारा नहीं लिए गए थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि अ.ल.ब.नि.का. द्वारा भी इन परिसंपत्तियों की लेखाबद्ध नहीं किया गया था।

**अनुशंसा: प.प्र.बो. के लिए अ.ल.ब.नि.का. द्वारा सृजित परिसंपत्तियों को औपचारिक रूप से लिया जाना चाहिए तथा लेखाबद्ध किया जाना चाहिए।**

अनुशंसा को प.प्र.बो. द्वारा स्वीकार किया गया था (मई 2015)।

<sup>1</sup>विमान का संचालन: बांधने, उथली जगह, स्थलों, आदि के माध्यम से जहाजों की चाल।

<sup>2</sup> नौवहन सहायता: दिन के प्रकाश, प्रकाश लाइटें, उठा हुआ बॉय तथा पत्तनों में जहाजों/पोतों के सुरक्षित नौवहन हेतु अन्य संकेतों जैसी सहायता

<sup>3</sup> जहाज कूली गतिविधियां: जहाजों/पोतों से कार्गो को चढ़ाने एवं उतारने से संबंधित गतिविधियां

### 2.1.4.2 प्रोफार्मा लेखे को तैयार न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली<sup>4</sup> में निर्धारित है कि जहाँ वाणिज्यिक या अर्ध-वाणिज्यिक आधार पर कार्य कर रहे कुछ सरकारी विभागों के संचालनों को रोकड़ आधारित सरकारी लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत उचित रूप से लाया नहीं जा सकता, वहाँ इकाईयों के अध्यक्षों को सरकार एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के बीच सहमत रूप से वाणिज्यिक रूप में सहायक प्रोफार्मा लेखे बनाने चाहिए। इसमें उपयुक्त विनिर्माण, व्यापार, लाभ और हानि खाते तथा तुलन पत्र शामिल है।

चूंकि प.प्र.बो. का संचालन वाणिज्यिक प्रकृति का है, 1989-90 और 1990-91 के लिए प्रोफार्मा लेखे इसके द्वारा तैयार किए गए थे। उसी की लेखापरीक्षा की गई और इस अभ्युक्ति के साथ कि 1989 से पूर्व के शेषों का अभिकलन नहीं किया गया था, अपेक्षित लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र जारी किए गए थे। प.प्र.बो. की वर्ष-वार वित्तीय स्थिति का 1991-92 से पता नहीं लगाया जा सका था क्योंकि 1990-91 से प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किए गए थे। प.प्र.बो. आज तक पूर्व की लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का अनुपालन करने में विफल रहा था। प.प्र.बो. ने बताया (जनवरी 2015) कि प्रोफार्मा लेखे इसलिए तैयार नहीं किए गए थे क्योंकि परिसंपत्तियों की संपूर्ण स्थिति को दर्शाते हुए कोई परिसम्पत्ति रजिस्टर नहीं था। यह सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 190(2) अनुसार नहीं था जोकि सभी परिसंपत्तियों के लेखाबद्ध होने को निर्धारित करता है।

**अनुशंसा: निर्धारित रूप से, प.प्र.बो. को प्रोफार्मा लेखे में वार्षिक वित्तीय स्थिति के प्रस्तुतीकरण हेतु तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।**

प.प्र.बो. द्वारा अभ्युक्ति एवं अनुशंसा को स्वीकार किया गया था (मई 2015)।

### 2.1.5 व्यय प्रबंधन

#### 2.1.5.1 पत्तन श्रमिकों के संदर्भ में श्रमबल तथा परिणामों तथा स्वीकृत तथ्य एवं अतिरिक्त स्टाफ भर्ती करने का पुर्नसंशोधन न किया जाना

अण्डमान श्रम बल (अं.श्र.ब.) में पोर्ट ब्लेयर में प.प्र.बो. द्वारा कार्यरत श्रमिक शामिल है ताकि वह प्रशासन तथा अन्य सरकारी विभागों/एस.सी.आई. पोतों के लिए जहाज से किनारे और किनारे से जहाज तक कार्गो को हैंडल कर सके। श्रम बल परिणामों<sup>5</sup> तथा स्वीकृत तथ्य<sup>6</sup> के लिए कार्गो के विभिन्न प्रकारों के लिए पत्तन श्रमिकों को प्रोत्साहनों के भुगतान के मानदंड 1975 में निर्धारित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि यंत्रिकृत कार्गो के विभिन्न प्रकारों को 1978 और 1989 के बीच शुरू किया गया था, प.प्र.बो. ने श्रमबल परिणामों तथा

<sup>4</sup> सा.वि.नि. -1963 का नियम 299 अब सा.वि.नि.-2005 का नियम 84

<sup>5</sup> श्रमबल परिणाम: गैंग में तैनात लोगों की संख्या

<sup>6</sup> स्वीकृत तथ्य: प्रति पारी में प्रति गैंग का न्यूनतम किया गया काम।

स्वीकृत तथ्य को संशोधित नहीं किया था जबकि समय-समय पर केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशासित वेतन के आधार पर उन्होंने प्रोत्साहनों का भुगतान किया था। कंटेनरीकृत कार्गो के लिए अलग से श्रमबल परिणाम तथा स्वीकृत तथ्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

- अं.श्र.ब. के श्रमिकों को प्रत्येक में 27 सदस्यों<sup>7</sup> के 12 गैंगों में कार्यरत रखा गया था जबकि अन्य मुख्य पत्तन गैंगों में 9 से 17 सदस्य थे।
- 2011-14 के दौरान गैंगों की तैनाती केवल 11 से लेकर 18 प्रतिशत तक थी परंतु पोर्ट ब्लेयर को छोड़कर अं.श्र.ब. श्रमिकों को उनके इष्टतम उपयोग के लिए घाट-शुल्क पत्तनों में स्थानांतरण नीति नहीं थी।
- 2011-14 के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रति गैंग द्वारा हैंडल किए गए कार्गो का औसतन परिणाम 47.65 एम.टी. तथा 84.70 एम.टी. था। प्रत्येक दिन की श्रमिक उत्पादकता केवल 4.84 कि.ग्रा. से लेकर 8.59 कि.ग्रा. के बीच थी जिसे एक वर्ष में हैंडल किए गए कार्गो के कुल परिणाम से तैनात श्रमिकों की कुल संख्या से भाग करके निकाला गया था।
- 2011-14 के दौरान, प्रत्येक एम.टी. पर सृजित राजस्व ₹89 से लेकर ₹94 तक था। जबकि प्रत्येक एम.टी. के कार्गो को हैंडल करने की लागत ₹3,149 से लेकर ₹3,676 तक थी।

उपरोक्त के अलावा, कंटेनरीकृत कार्गो को हैंडल करने के लिए मानदंडों की अनुपस्थिति के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ था जिसे कि अनुवर्ती पैराग्राफ में विस्तृत रूप से दिया गया है।

### **2.1.5.2 कंटेनरीकृत कार्गो के लिए प्रोत्साहन भुगतान पर ₹1.80 करोड़ का परिहार्य व्यय**

भा.स. द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहन योजना जोकि विशेष रूप से केवल मैनुअल कार्गो हैंडलिंग के लिए बनाई गई थी, इसके अनुसार नवम्बर 1975 में निर्धारित मानदंडों के आधार पर अं.श्र.ब. को प्रोत्साहन भुगतान किए गए थे। संबंधित आदेश में खुले ट्रक, ट्राली, ट्रेलरों, फोर्कलिफ्ट तथा चलायमान घाट क्रेन जैसे आधुनिक उपकरण के साथ मानदंडों का पुर्ननिर्माण निर्धारित किया गया था।

1978 तथा 1989 के बीच कार्गो हैंडलिंग के लिए मशीनीकृत मशीनरी/उपकरण अर्थात् 6-25 टन घाट क्रेनों, 45 टन की पहुँच वाले स्टेकर, 3-25 टन के फोर्कलिफ्ट आदि के प्रापण के पश्चात् 1991 में पोर्ट ब्लेयर में कंटेनरीकृत कार्गो सेवाओं की शुरुआत की गई थी। इसलिए पोर्ट ब्लेयर में कंटेनरीकृत कार्गो की हैंडलिंग मैंगलौर एवं तूतीकोरिन जैसे अन्य पत्तनों के समान थी तथा किसी हैड लोड की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि, प.प्र.बो. या

<sup>7</sup> प्रत्येक गैंग में 2 मुख्य कार्यकर्ता, 2 सिग्नल-मैन, 3 विचमैन, एवं 20 मजदूर शामिल हैं

प्रशासन द्वारा कंटेनरीकृत कार्गो को हैंडल करने के लिए कोई स्वीकृत तथ्य या श्रमिक परिणाम निर्धारित नहीं किया गया था, प्रोत्साहन भुगतान उद्देश्य हेतु हैंडल किए गए कुल भार के आधार पर इसे सामान्य कार्गो के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। भारत के अन्य पत्तनों में, कंटेनरीकृत कार्गो को हैंडल करने के लिए तथ्य को या तो हैंडल किए गए कंटेनरों की संख्या या फिर प्रत्येक श्रमिक द्वारा हैंडल किए गए वजन पर निर्धारित किया जाता था तथा गैंग का संयोजन 6-12 श्रमिकों के बीच होता था। परंतु प.प्र.बो. में 27 सदस्यों का पूरा गैंग प्रत्येक कंटेनर में लदान/उतराई के लिए तैनात किया गया था। यह भी पाया गया था कि कंटेनर को तट से जहाज या जहाज से तट तक स्थापित करने के लिए प्रति हैच<sup>8</sup> प्रति शिफ्ट के लिए अधिकतम 12 श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। इससे पता चलता है कि कंटेनरीकृत कार्गो को हैंडल करने के लिए प्रति गैंग प्रति शिफ्ट में कम से कम 15 अं.श्र.ब. कार्यकर्ताओं (27-12 सदस्य) की अतिरिक्त तैनाती की गई थी।

फोटो-1



फोटो-2



**जहाज के साथ लगाई गई, क्रेन की सहायता से कंटेनर में लदान**

8 हैच: कार्गो को रखने के लिए वाटर टाइट कवर के साथ जहाज के डेक में फीट करना

इस प्रकार, 12 सदस्यों के स्थान पर 27 सदस्यों की तैनाती तथा कंटेनरीकृत कार्गो की शुरूआत पर श्रमिक परिणाम तथा स्वीकृत तथ्यों के गैर-संशोधन के कारण, 2011-14 के लिए प्रोत्साहन भुगतान के प्रति प.प्र.बो. द्वारा ₹1.80 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया था। (अनुबंध-II)।

कंटेनरीकृत कार्गो को हैंडल करने के लिए अतिरिक्त श्रमिकों की तैनाती पर अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए, प.प्र.बो. ने बताया कि 6-12 श्रमिकों की जगह पर 27 सदस्य तैनात किए गए थे, क्योंकि श्रमिक यूनियन, गैंग की संख्या को कम करने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी।

**अनुशंसा: प.प्र.बो. को विभिन्न प्रकार के कार्गो के लिए पत्तन श्रमिकों को प्रोत्साहनों के भुगतान के लिए श्रमिक परिणाम तथा स्वीकृत तथ्यों के मानदंडों को फिर से देखना चाहिए तथा कंटेनरीकृत कार्गो के लिए श्रमिक परिणाम तथा स्वीकृत तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए।**

प.प्र.बो. ने अभ्युक्ति एवं अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2015)।

### **2.1.5.3 ₹1.83 करोड़ की राशि के अतिरिक्त वेतनों का परिहार्य भुगतान**

अं.श्र.ब. के श्रमिक जहाज से तट तथा तट से जहाज तक कार्गो हैंडल करते हैं। प.प्र.बो. के तट मजदूरों को तट तथा गोदामों के बीच सरकार के स्वामित्व वाले जहाजों के बीच कार्गो को हैंडल करने के लिए तैनात किया गया था।

जून 1985 से, नवम्बर 1975 में अं.श्र.ब. के लिए शुरू की गई प्रोत्साहन योजना को तटीय मजदूरों तक पहुंचाया गया था। प्रोत्साहन योजना के अनुसार, श्रमिक रविवार तथा अन्य औद्योगिक अवकाशों पर उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन के पात्र थे। हालांकि, अभिलेखों से पता चला कि अं.श्र.ब. के अंतर्गत सभी श्रमिकों तथा सभी तटीय मजदूरों को प्रत्येक वर्ष सभी रविवारों तथा औद्योगिक अवकाशों के लिए अतिरिक्त वेतनों का भुगतान किया गया था। यह उनके द्वारा हैंडल किए गए कार्गो से निरपेक्ष था। 2011-14 की अवधि के दौरान रविवारों एवं अवकाशों के 190 दिनों में से पोर्ट ब्लेयर में जहाज केवल 91 दिनों के लिए रुके थे तथा कार्गो को 3352 श्रमिक शिफ्टों में हैंडल किया गया था। हालांकि, संवीक्षा से पता चला कि 8416 श्रमिक शिफ्टों के प्रति ₹2.64 करोड़ की राशि का भुगतान संपूर्ण 190 दिनों के लिए किया गया था जिसके कारणवश उनके द्वारा बिना काम करे ही ऐसे 99 रविवारों तथा अवकाशों के लिए ₹1.58 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ था। (अनुबंध-III)। इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान 784 तटीय मजदूरों के प्रति ₹ 0.25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया था। (अनुबंध-IV)

प.प्र.बो. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा उन रविवारों तथा अवकाशों की अतिरिक्त वेतनों को बंद करने के लिए आदेश जारी किया जिसमें पत्तन में जहाज रुका नहीं था।



### 2.1.5.4 रविवार एवं अवकाश पर प्रोत्साहन राशि का अतिरिक्त भुगतान

प्रोत्साहन राशि भुगतान संबंधी वर्कशीट की लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि प्रत्येक मजदूर के लिए प्रोत्साहन राशि की गणना करते समय प्रति गैंग प्रति पारी के लिए निर्धारित मानदण्ड के विरुद्ध उठाये अतिरिक्त भार<sup>9</sup> को यथानुपात मजदूरी प्रति मी.ट. से गुणा कर निकाला जाता था। रविवार एवं अवकाश के मामले में मजदूरों एवं तटीय मजदूरों को उनके सामान्य मजदूरी के अतिरिक्त यथानुपाती दर से दुगुनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी। वर्ष 2011-14 की अवधि में इस मद पर मजदूरों एवं तटीय मजदूरों को क्रमशः ₹98.10 लाख तथा ₹17.38 लाख का अतिरिक्त भुगतान (अनुबंध-V) किया गया था।

पी.एम.बी. ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारा (मई 2015) तथा कहा कि वसूली प्रतीक्षित थी।

### 2.1.5.5 अपूर्ण प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर ₹1.47 करोड़ का निष्फल व्यय

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह जलीय जैविक विविधता के लिए विख्यात है। पोर्ट संचालन से वातावरण प्रभावित होने की संभावना रहती है। हदों में बर्थ संख्या 3 तथा 4 के निर्माण की स्वीकृति दिए जाते समय (मार्च 1992) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प.व.मं.) ने कुछ पर्यावरण सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया था। परिणामस्वरूप, पी.एम.बी. ने नवी पंचवर्षीय परियोजना में एक बंदरगाह संरक्षक एवं प्रदूषण नियंत्रण योजना को शामिल किया था जिसमें दो बड़े घटक यथा एक स्टील डम्प सलेज<sup>10</sup> बार्ज का निर्माण जिसमें पोतों से निकलने वाली बिलज<sup>11</sup> का एकत्रीकरण तथा स्किमर्स<sup>12</sup> के माध्यम से तेल निकालने एवं तेल प्रदूषण नियंत्रण परिशोधन संयंत्र का निर्माण करना शामिल थे।

सलेज बार्ज को पी.एम.बी. द्वारा अधिप्राप्त किया जाना था तथा ए.एल.एच. डब्ल्यू द्वारा बार्ज पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण को स्थापित किया जाना था तथा एक इनसिनेरेटर<sup>13</sup> रोड का निर्माण तट (हदो हवार्फ) पर किया जाना था। पी.एम.बी. ने एक 100 टन सलेज बार्ज को ₹50 लाख की कीमत पर अधिप्राप्त किया (2003) जिसको ए.एल.एच.डब्ल्यू को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना हेतु सौंप दिया था। ए.एल.एच.डब्ल्यू ने ₹91.92 लाख की लागत से सलेज बार्ज तथा हदों पर इनसिनेरेटर रोड का कार्य पूर्ण किया (मार्च 2007) तथा इन दोनों को पी.एम.बी. को अगस्त 2009 में सौंपा गया था। तत्पश्चात सलेज बार्ज के अनुरक्षण एवं सर्वे पर पी.एम.बी. द्वारा ₹4.98 लाख का व्यय किया गया था। तथापि, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण को मानव शक्ति की संस्वीकृत अनुपलब्धता के कारण मई 2015 तक प्रयोग में नहीं लाया जा सका था। 'सागर शुचि' बार्ज खुले में खराब मौसम के प्रभाव से जंग लगने

9 वेतन में मूलवेतन, ग्रेड वेतन, महंगाई भत्ता और अंडमान विशेष प्रतिपूरक भत्ता

10 सलेज- अपशिष्ट पदार्थ अथवा सीवेज आदि

11 बिलज : पोत के तल में एकत्र होने वाला दुर्गंधयुक्त काला पानी

12 ऑयल स्किमर्स : द्रव्य की सतह पर तैरता तेल को हटाने वाला उपकरण

13 इनसिनेरेटर : अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया जो कार्बनिक पदार्थों जिसमें अपशिष्ट पदार्थ शामिल होते हैं की दहन प्रक्रिया शामिल होती है।

के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। तथ्यों एवं आंकड़ों से सहमत होते हुए पी.एम.बी. ने बताया (जनवरी 2015) कि उपकरण उपयोग लायक नहीं था। इस प्रकार पी.एम.बी. द्वारा समय रहते प्रभावी कार्यवाही न किए जाने के कारण न केवल ₹1.47 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ बल्कि प.व.मं. द्वारा निर्धारित पर्यावरण संरक्षण उपाय भी गैर-कार्यान्वित रहे।

पी.एम.बी. ने आगे बताया (मई 2015) कि पोत का उपयोग करने हेतु पोर्ट ब्लेयर में रिसाव की कोई घटना ही नहीं हुई। उत्तर से निष्फल व्यय को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। पी.एम.बी. ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (मई 2015)।

फोटो-3



फोटो-4



प्रदूषण नियंत्रण उपकरण सागरशुचि की वर्तमान स्थिति

### 2.1.5.6 सी.एस.टी. के रूप में ₹10.54 लाख का अतिरिक्त भुगतान

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप में मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.) का कोई प्रावधान नहीं है लेकिन अन्य कर जैसे चुंगी, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.), फ्रेट, संघ क्षेत्र का स्टैम्प शुल्क तथा केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत सेवा कर लागू थे। के.बि.क. की दर 01 जून 2008 से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी गई थी।

पी.एम.बी. ने दो हीमैन हाई स्कैन एक्सरे बैगजे जांच प्रणाली (एक्स. बी.आई.एस.) जुलाई 2012 में ₹1.13 करोड़ की कुल लागत पर खरीदा था। इस क्रय के लिए के.बि.क. की लागू दर दो प्रतिशत की बजाए 12.5 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹10.54 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

पी.एम.बी. ने लेखापरीक्षा को स्वीकारते हुए (मई 2015) लेखापरीक्षा से अनुरोध किया कि उक्त मामले में के.बि.क. की दर का सत्यापन किया जाए। चूंकि के.बि.क. की दर दो प्रतिशत थी, अतः संबंधित आपूर्तिकर्ता से पी.एम.बी. द्वारा अतिरिक्त भुगतान की वसूली की जानी आवश्यक है।

### 2.1.6 राजस्व प्रबंधन

पी.एम.बी. बंदरगाह उपयोक्ताओं से अपनी सेवाओं तथा सुविधाओं के उपयोग के बदले वेसेल रिलेटेड चार्जेज (वी.आर.सी.)<sup>14</sup>, कार्गो रिलेटेड चार्जेज (सी.आर.सी.)<sup>15</sup> तथा संपदा किराये की वसूली करता है।

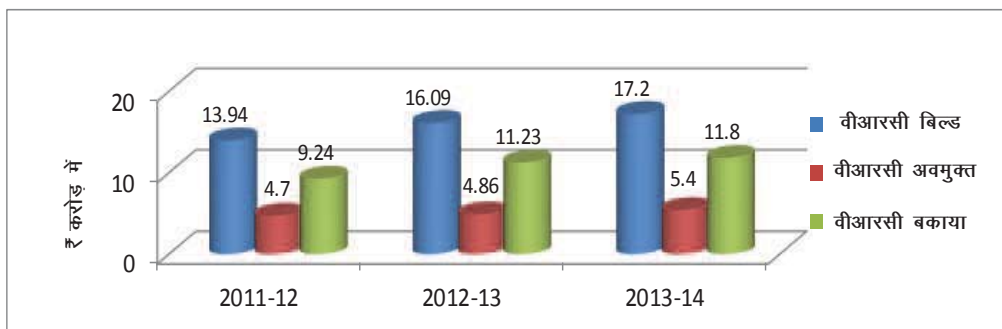
#### 2.1.6.1 वी.आर.सी./सी.आर.सी. की प्राप्ति में विलम्ब

भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 की धारा 43 निर्धारित करती है कि पत्तन में आए किसी भी पोत की निकासी तब तक अनुमेय नहीं होगी जब तक पोत के मालिक/अधिकारी द्वारा पत्तन की सारी देयताएं पूरी चुकाई न जाएं। उपरोक्त अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन में पी.एम.बी. द्वारा बिना पत्तन की सारी देयताओं को पूर्ण करे ही पोत की निकासी की अनुमति दे दी थी। लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि पोतों के चले जाने के बाद की तिथि से औसतन दो से चार सप्ताह पश्चात बिल तैयार किये जाते थे तथा इनका भुगतान औसतन एक से डेढ़ महीने बाद किया जाता था जिसके परिणामस्वरूप और अधिक देर होती थी। 2011-12 से 2013-14 की अवधि में वी.आर.सी. एवं सी.आर.सी. की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है।

<sup>14</sup> वी.आर.सी. के अन्तर्गत पोर्ट बकाया, पाइलटेज प्रभार, टग प्रभार, बर्थ किराया प्रभार, लंगर प्रभार, स्थानांतरण प्रभार, रात्रि नेवीगेशन प्रभार, जल प्रभार तथा बोट के लिए लंगर प्रभार आदि।

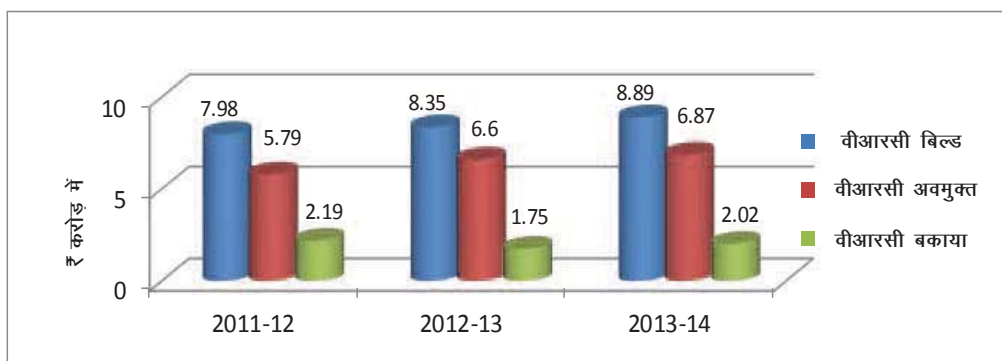
<sup>15</sup> सी.आर.सी. के अंतर्गत घाट प्रभार, तटीय गैंग प्रभार, कार्गो हैंडलिंग उपकरण प्रभार, कंटेनर हैंडलिंग एवं भंडारण प्रभार, लाइसेंस शुल्क, बंकरिंग प्रभार, टोल कर, तुलाई एवं छुट्टियाँ प्रभार, आदि शामिल हैं।

चार्ट-6



वी. आर.सी. की स्थिति

चार्ट-7



सी.आर.सी. की स्थिति (आने वाले कार्गो हेतु कोई राशि बकाया नहीं थी।)

चार्ट केवल तीन वर्षों की बकाया राशि को दर्शाता है, जबकि 31 मार्च 2014 को पो.स. प्र. तथा का.सा.प्र. का कुल बकाया क्रमशः ₹106.54 करोड़ एवं ₹13.45 करोड़ था, प्रमुख चूककर्ता डी.एस.एस., एस.सी.आई, सी.सी.एस.<sup>16</sup> और अन्य सरकारी विभाग थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि पी.एम.बी. ने चूककर्ताओं पर जुर्माना नहीं लगाया था क्योंकि प्रभारों को लगाने के लिए पो.प.मं. द्वारा जारी अधिसूचना में ऐसा प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया था।

उत्तर में पी.एम.बी. ने बताया कि बिलों को प्रस्तुत करने तथा भुगतानों को प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। पो.सं.का. से संबंधित वाउचरों की प्रोसेसिंग पोत के प्रस्थान के पश्चात ही आरंभ होती थी क्योंकि पी.एम.बी. को पायलट अधिकारी से आवश्यक सूचना प्राप्त करनी होती है जिसमें कम से कम एक हफ्ते का समय लगता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारतीय पत्तन अधिनियमों, 1908 के अंतर्गत पो.प.मं. द्वारा अधिसूचित रूप में पो.सं.प्र. को प्रस्तुत किया जाना था तथा कथित अधिनियम की धारा 43 प्रस्थान से पूर्व सभी पत्तन बकाया राशियों की वसूली निर्धारित करता है। पी.एम.बी. ने सा.प्र. पर अभ्युक्तियों को यह बताते हुए स्वीकार किया (जनवरी 2015) कि बिल बनाने में विलंब हुआ था क्योंकि बिलिंग की प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत नहीं थी।

<sup>16</sup> उपभोक्ता सह-सहकारी समितियां

**अनुशंसा: भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 में निर्धारित रूप से पी.एम.बी. को पत्तनों से पोतों के प्रस्थान से पूर्व पो.सं.का./का.सं.का. की वसूली तथा दावों को प्रस्तुत करना चाहिए।**

अनुशंसा को स्वीकार करते हुए, यह बताया गया कि मई 2015 की संशोधित ड्राफ्ट अधिसूचना में जुर्माना/ब्याज को लगाए जाने के लिए प्रावधान किया गया था।

### 2.1.6.2 पत्तन उपयोगकर्ताओं को अनुचित लाभ

अप्रैल 2008 से, प्रतिभूति जमा (लेनदेन की संख्या के आधार पर निर्धारित) को पी.एस.बी. द्वारा प्राप्त किया जाता था। सावधि जमा दरों (सा.ज.द.) वाली केवल उन्हीं पोत परिवहन कम्पनियों को पत्तन बकाया दिए बिना अपने पोत को चलाने की अनुमति थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से स्पष्ट हुआ कि सभी निजी उपयोगकर्ताओं तथा मुख्य चूककर्ताओं अर्थात् पो.प.से. नि., एस.सी.आई., आदि से प्रतिभूति जमा प्राप्त नहीं की गई थी। यह भी पाया कि पुनरावृत्त चूककर्ताओं से कोई प्रतिभूति जमा प्राप्त नहीं की गई थी तथा ऐसे मामले भी पाए गए थे जहाँ बकाया राशि प्राप्त प्रतिभूति राशि से अधिक थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	शिपिंग कम्पनी का नाम	बकाया अवधि	राशि (₹) (पो.सं.प्र.)	अधिकतम लंबिता	प्रतिभूति जमा (₹)
1.	मैसर्स मीनाक्षी शिपिंग	अप्रैल-09 से लेकर मार्च-14 से पूर्व	16,36,224	6 वर्ष	कोई सुरक्षा नहीं
2.	मैसर्स गति शिपिंग	अक्टूबर-13 से नवम्बर-13	404240	1वर्ष	5,00,000
3.	मैसर्स मैरिन एन केयर	जनवरी-09 से लेकर नवम्बर -13 से पूर्व	448384	6 वर्ष	कोई सुरक्षा नहीं
4.	मैसर्स आयशा शिपिंग	मई-11 से फरवरी-14	257557	3.5 वर्ष	कोई सुरक्षा नहीं
5.	मैसर्स जेडवेट शिपिंग सेवाएं	अक्टूबर.12 से मार्च-13	114170	2 वर्ष	1,42,583
6.	मैसर्स कैप्टन बाथ	अप्रैल-09 से मार्च-14 से पूर्व	382143	6 वर्षों से अधिक	कोई सुरक्षा नहीं
<b>कुल</b>			<b>32,42,718</b>		

पी.एम.बी. द्वारा अनुस्मारक जारी करने के अलावा कोई प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि उसके पास कोई कानूनी शक्तियां नहीं थीं जिसके कारण विशाल संचय हुआ था।

**अनुशंसा: दोषी जहाज मालिकों के पोतों को ए.एन.आई. के पत्तनों के भीतर चलाए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सभी पत्तन उपयोगकर्ताओं से प्राप्त लेनदेनों की संख्या प्रतिभूति जमा के अनुरूप होनी चाहिए।**

पी.एम.बी. ने अभ्युक्ति एवं अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2015)।

### 2.1.6.3 बकाया गैंग प्रभार

बकाया गैंग प्रभारों के रूप में ₹7.15 करोड़ की राशि फरवरी 2015 तक एस.सी.आई. एवं पो.प.से.नि. से लंबित थी जोकि क्रमशः 1989 एवं 1990 से लंबित थी (2011-14 से संबंधित

₹1.01 करोड़)। अप्रैल 2011 से मार्च 2013 की अवधि हेतु गैंग प्रभारों को एक वर्ष<sup>17</sup> के औसतन विलंब के पश्चात् नियंत्रक, ए.एल.एफ. द्वारा वरीय माने गए थे। पो.प.से.नि. तथा एस.सी.आई. के प्रति बकाया राशि को दर्शाने वाली कोई सूची अनुरक्षित नहीं की गई थी तथा उनकी वसूली हेतु कोई अनुस्मारक जारी नहीं किए गए थे। गैंग प्रभारों को प्रस्तुत एवं वसूली करने में सी.ए.एल.एफ./पी.एम.बी. के निरुत्साही दृष्टिकोण के कारण इसका अधिक संचय हुआ था।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए यह बताया गया था कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ₹7.15 करोड़ समेत गैंग प्रभारों के प्रति सभी बिलों को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था। वसूली प्रतीक्षित थी।

#### **2.1.6.4 पो.सं.प्र. की दरों में संशोधन न किए जाने के कारण ₹11.81 करोड़ के राजस्व की हानि**

प्रायः पत्तन 3–5 वर्षों<sup>18</sup> के अंतराल पर पो.सं.प्र. तथा का.सं.प्र. को संशोधित करते हैं। पी.एम.बी. की संशोधन हेतु ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, पी.एम.बी. अपने द्वारा प्रदत्त पत्तन सेवाओं के लिए प्रभारों को निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत नहीं था। प्रक्रिया में हितधारकों के साथ चर्चा करके प्रभारों को निर्धारित करने के लिए पी.एम.बी. द्वारा प्रस्ताव की शुरुआत करना शामिल था। बोर्ड से संस्वीकृति के पश्चात्, प्रस्ताव को वेटिंग/संस्वीकृति हेतु प्रशासन को प्रेषित किया जाना था, तथा उसके बाद अंतिम स्वीकृति तथा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना दिए जाने के लिए पो.प.से.नि. को संचरण किया जाएगा।

1998 में टैरिफ के प्रारंभिक निर्धारण की तिथि से 14 वर्षों की समाप्ति के पश्चात् भी 2011–12 तक पी.एम.बी. द्वारा पो.सं.प्र. के संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की गई थी। पो.सं.प्र. में 25 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव जुलाई 2011 की बोर्ड की बैठक में स्वीकृत किया गया था, तथा प्रशासन की स्वीकृति पर प्रस्ताव को पो.प.मं. के पास भेज दिया गया था। पो.प.मं. ने बताया (मई 2013) कि या तो प्र.प.द.सू.प्रा.<sup>19</sup> के आधार पर व्यापक प्रस्ताव या किसी अन्य उपयुक्त तंत्र को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा। ऐसा नहीं किया गया था तथा प.सं.प्र. हेतु दरों को अभी तक संस्वीकृत (फरवरी 2015) नहीं किया गया था।

पी.एम.बी. ने 1998 में निर्धारित दर सूची के अनुसार प.सं.प्र. के कारण 2011–14 के दौरान ₹47.23 करोड़ की राशि के बिल प्रस्तुत किए गए थे तथा यदि 25 प्रतिशत की वृद्धि को समय पर कार्यान्वित कर दिया होता तो उसके बाद की अवधि के दौरान पी.एम.बी. अतिरिक्त ₹11.81 करोड़ (₹47.23 करोड़ का 25 प्रतिशत) की राशि अर्जित कर लेता।

<sup>17</sup> एक से लेकर 29 महीनों तक

<sup>18</sup> मॉरमुगाओ पत्तन न्यास अपनी दरें तीन वर्षों में संशोधित करता है तथा न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास अपनी दरें पाँच वर्षों के बाद संशोधित करता है।

<sup>19</sup> प्रमुख पत्तनों हेतु दर सूची प्राधिकरण

पी.एम.बी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मई 2015 ) और बताया कि मार्च 2015 में उनके बोर्ड ने 1998 से आज तक एक प्रतिशत और उसके पश्चात दो प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि के साथ प.सं.प्र. को संशोधित करने का निर्णय लिया था।

**अनुशंसा: पी.एम.बी. को विभिन्न पत्तन सेवाओं के लिए प्रभारों के आवधिक संशोधन हेतु नियम बनाने चाहिए तथा भारत के अन्य पत्तनों के अनुसार राजस्व में वृद्धि तथा तीव्र वसूली हेतु उचित तंत्र अपनाना चाहिए।**

पी.एम.बी. ने अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2015)।

### 2.1.6.5 का.सं.प्र. हेतु टैरिफ का गैर-कार्यान्वयन

टैरिफ समेत का.सं.प्र.<sup>20</sup> हेतु नियमावली सबसे पहले अप्रैल 1992 में प्रकाशित हुई थी तथा पो.प.मं. की अधिसूचना के अनुसार 2004<sup>21</sup> में 12 वर्षों के पश्चात इसमें संशोधन किए गए थे। इस प्रार्थना पर कि सुनामी के पश्चात् राहत एवं पुर्नवास निर्माण कार्य कार्याधीन थे, प्रशासन ने मंत्रालय से मार्च 2006 तक संशोधित का.सा.प्र. के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निवेदन किया था। तदनुसार, मंत्रालय ने अपने कार्यान्वयन को जून 2006 तक स्थगित कर दिया था। उसके पश्चात् अण्डमान वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर ने का.सं.प्र. की संशोधित दरों में एकाएक वृद्धि के प्रति पो.प.मं. के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया। उसके पश्चात्, मंत्रालय ने निर्देश दिया (दिसम्बर 2006) कि 2004 अधिसूचना के कार्यान्वयन को आगे की अधिसूचना तक निलम्बन में रखा जाना चाहिए। आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यदि 2004 अधिसूचना को कार्यान्वित किया जाता तो पी.एम.बी. अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक की अवधि के दौरान ₹12.44 करोड़ अर्जित कर सकता था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

मदों का नाम	अर्जित नहीं किया गया राजस्व (₹ करोड़ में)
स्थान का अवंटन (लाइसेंस शुल्क)	0.49
यात्री पथकर	1.82
कंटेनर हैंडलिंग प्रभार	2.93
निजी जहाज कुलियों को लाइसेंस जारी करना (लाइसेंस/नवीकरण शुल्क)	0.20
घाट/जेटी जहाज कुली प्रभार (अं.श्र.ब. स्टाफ)	1.64
पत्तन उपकरण प्रभार	1.66
घाट-भाड़ा प्रभार	2.69
भंडारण एवं विलम्ब शुल्क प्रभार	1.01
<b>कुल</b>	<b>12.44</b>

<sup>20</sup> लैंडिंग स्थानों, घाटों, बांधों, गोदामों, शेडों तथा अन्य विविध सेवाओं के उपयोग हेतु नियम का निर्धारण

<sup>21</sup> दिनांक 3.12.2004 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 786(ई)

पी.एम.बी. ने बताया कि दिसम्बर 2004 में जारी की गई अधिसूचना को निलम्बित रखा गया था। यह कानून एवं न्याय मंत्रालय के विचार के उल्लंघन में था जिसमें वर्गीकृत रूप से समझाया गया (जून 2008) था कि 2004 अधिसूचना की दरों को निलम्बित रखा जाना वैध नहीं था तथा इसलिए 2004 अधिसूचना की दरें लागू होती थीं।

हालांकि, तथ्य था कि का.सं.प्र. अप्रैल 1992 में अधिसूचित दरों के अनुसार प्रभारित किया जा रहा था।

**अनुशंसा: सरकार को आगे हानि से बचाने के लिए किसी वैधानिक रूप से मान्य संशोधन या दिसम्बर 2004 में संशोधित दरों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।**

पी.एम.बी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति तथा अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2015)।

### **2.1.6.6 ₹2.74 करोड़ के जहाज कुली हैंडलिंग प्रभारों की वसूली न किया जाना**

निजी जहाजों द्वारा लाए गए कार्गो को संभालने के लिए अक्टूबर 1993 में निजी जहाज कुलियों को लाया गया था। नवम्बर 1996 में, प्रशासन ने जहाज कुली हैंडलिंग प्रभार<sup>22</sup> की दरें निर्धारित की थी जिसे अ.नि.द्वी.स. के पत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग हेतु लाइसेंसयुक्त निजी जहाज कुलियों से वसूल किया जाना था।

पी.एम.बी. ने निजी जहाज कुलियों के साथ अनुबंध किए तथा अ.नि.द्वी.स. के पत्तनों पर निजी जहाज वालों के कार्गो को संभालने के लिए लाइसेंस जारी किए थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अनुबंधों में निर्धारित रूप से 'जहाज कुली हैंडलिंग प्रभार' की वसूली नहीं की गई थी। यद्यपि, प्रतिवेदन के अंतर्गत अवधि 2011-14 है, यह बताना आवश्यक है कि पी.एम.बी. नवम्बर 1996 से लेकर मार्च 2008 तक ₹1.93 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा था (अनुबंध –VI)। कथित प्रभारों की वसूली केवल अप्रैल 2008 से शुरू हुई थी परंतु अप्रैल 2008 से मार्च 2014 तक ₹81.06 लाख की कम वसूली हुई थी (अनुबंध –VII)। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण हुआ था कि लाइसेंस धारक ने मासिक हैंडलिंग कार्गो तथा उनके द्वारा संबंधित पत्तनों के पत्तन प्रभारी के लिए तैनात किए गए समूहों की संख्या को सूचित नहीं किया था जबकि ऐसा करना अनुबंध में निर्धारित था। लाइसेंसधारक द्वारा कुल हैंडलिंग कार्गो के संदर्भ में अ.नि.द्वी.स. के किसी पत्तन में वसूले जाने वाली राशि तथा वास्तव में वसूली गई राशि के मिलान के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

पी.एम.बी. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया। उन्होंने यह भी बताया कि जहाज कुली हैंडलिंग प्रभारों के बिलों की जांच तीन अलग स्रोतों द्वारा की जा रही थी ताकि भविष्य में कम वसूली से बचा जा सके। परंतु, तथ्य यह था कि ₹2.74 करोड़ की राशि के जहाज कुली हैंडलिंग प्रभार मई 2015 तक वसूल नहीं किए गए थे।

<sup>22</sup> जहाज कुली हैंडलिंग प्रभारों को निजी जहाज कुली द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर लगाया जाता है।



### 2.1.6.7 ₹1.21 करोड़ के राजस्व को जमा कराने में विलम्ब

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली का नियम 6 प्रावधान करता है कि राजस्व या प्राप्ति या सरकारी बकाया के रूप में सरकारी कार्यालयों द्वारा प्राप्त अथवा को प्रदान किए गए सभी धनों का, बिना अनुचित विलम्ब के, सरकारी लेखे में शामिल किए जाने हेतु प्राधिकृत बैंक में पूरा भुगतान किया जाएगा।

भारत सरकार 01 जून 2010 को पोर्ट ब्लेयर में अपने मुख्यालय सहित मुख्य पत्तन के रूप में अ.नि.द्वी. में पत्तन की स्थापना करने की घोषणा की थी तथा इसे पोर्ट ब्लेयर पत्तन न्यास (पो.ब्लै.प.न्या.) का नाम दिया था। पो.ब्लै.प.न्या. की घोषणा के पश्चात न तो मंत्रालय और न ही प्रशासन द्वारा पत्तन को कोई निधियां प्रदान की गई थीं। प.प्र.बो. तथा ए.एल.एफ. का पूरा व्यय 13 सितंबर 2010 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक चालू खाता खोलकर पहले के पत्तन द्वारा उत्पन्न राजस्व से पूरा किया गया था। तथापि, 01 जून 2010 की अधिसूचना को पो.प.मं. द्वारा अस्थगित रखा गया था तथा जून 2010 से पहले की यथास्थिति का फरवरी, 2011 के बाद से अनुरक्षण किया गया था। फरवरी, 2011 से प.प्र.बो. योजनागत तथा गैर-योजनागत शीर्षों के अंतर्गत वार्षिक बजट के माध्यम से प्रशासन से नियमित निधि प्राप्त कर रहा था। इस प्रकार, भुगतानों एवं प्राप्तियों के नियम 6 के अनुसार फरवरी, 2011 को ₹1.21 करोड़ का शेष उपरोक्त चालू खाते में पड़ा है जिसे बिना विलम्ब के सरकारी खाते में जमा किया जाना चाहिए था। तथापि, ₹1.21 करोड़ को 26 महीनों से अधिक के बीत जाने के पश्चात केवल 03 मई 2015 में जाकर ही सरकारी खाते में जमा करवाया गया था। इसका परिणाम चार प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर परिकलित ब्याज के माध्यम से सरकार को ₹10.48 लाख की हानि के रूप में हुआ।

प.प्र.बो. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (मई 2015)।

### 2.1.6.8 भूमि/पत्तन क्षेत्र स्थान का आवंटन

प.प्र.बो. के पास उपलब्ध भूमि का सरकारी विभागों तथा निजी दलों को आवंटन किया गया था। आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किए गए थे। पत्तन उपभोक्ताओं से लिखित अनुरोधों पर प.प्र.बो. द्वारा तीन महीनों की अवधि हेतु अस्थायी रूप से खुले/ढके हुए स्थानों के उपयोग की आवश्यक अनुमति प्रदान की गई थी। निजी दलों को आगे के तीन महीनों हेतु बार-बार विस्तार प्रदान किए गए थे। जबकि सरकारी विभागों ए.एन.आई. आई.डी.सी.ओ., मैसर्स सी.सी.एस.लि. को निरंतर अथवा उस समय तक जब तक वह स्वयं स्थानों को खाली न कर दे, स्थानों को अधिकृत करने को अनुमत किया गया था। अन्य पतनों के विपरीत प.प्र.बो. की कोई भूमि प्रबंधन नीति नहीं है जो भूमि के गैर-सीमांकन के कारण थी। यह बताया गया कि प.प्र.बो. से संबंधित क्षेत्रों, जिसे पत्तन उपयोगकर्ताओं को पट्टे पर दिया जा सकता था, की अभी भी पहचान नहीं की गई थी।

चूंकि प.प्र.बो. के पास भूमि आवंटन नीति तथा वैधिक शक्तियां नहीं थी इसलिए वह लागू लाईसेंस शुल्क वसूलने में विफल रहा।

**अनुशंसा: प.प्र.बो. के हित की सुरक्षा तथा राजस्व के सर्वर्धन हेतु जल्द से जल्द भूमि नीति तैयार की जानी चाहिए।**

प.प्र.बो. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति तथा अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2015)। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने भूमि के सीमांकन हेतु कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है तथा मामले को संबंधित जिला आयुक्त के साथ उठाया गया है।

### 2.1.7 आंतरिक नियंत्रण

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, विधियों, नियमों, विनियमों तथा आदेशों की अनुपालना का उचित आश्वासन तथा धोखे तथा कुप्रबंधन से सुरक्षाएं प्रदान करनी चाहिए तथा इसे उच्च प्राधिकारियों को विश्वसनीय वित्तीय तथा प्रबंधन सूचना सुनिश्चित करना चाहिए। नियंत्रण कार्यों में, प्रलेखन, भुगतानों का प्राधिकरण तथा स्वीकृति, कर्तव्यों का वियोजन, समाधन एवं सत्यापन, निरीक्षण तथा लेखापरीक्षा, संचालन निष्पादन की समीक्षा तथा मॉनीटरिंग शामिल हैं।

यद्यपि, प.प्र.बो. के बोर्ड का 1983 में गठन तथा 2000 में पुनर्गठन किया गया था फिर भी बोर्ड की शक्ति तथा उत्तरदायित्व के संबंध में कोई नियम एवं विनियम तैयार अथवा निर्धारित नहीं किए गए थे। आयोजित की जाने वाली आवधिक बैठकों की अनुसूचि नहीं बनाई गई थी। 2011-14 के दौरान, बोर्ड ने जुलाई 2011 तथा फरवरी 2012 में दो बार बैठक की थी। बोर्ड ने प.प्र.बो. द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों के सुधार हेतु किसी समिति/उप-समिति का कभी गठन नहीं किया था। अपनी वर्तमान स्थिति के कारण प.प्र.बो. अपने संचालन हेतु तथा राजस्व सृजन के लिए नियमों/विनियमों/प्रभारों को तैयार नहीं कर सका था।

प.प्र.बो. में, यह सुनिश्चित करने हेतु की उपयुक्त जांच तथा नियंत्रणों का उपयोग किया गया था तथा चोरी, हानि, दुरुपयोग आदि से बचने हेतु उपयुक्त प्रणाली स्थापित थी, कोई आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं था। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के अभाव में, प.प्र.बो. का बोर्ड अथवा प्रबंधन प.प्र.बो. के विभिन्न स्कंधों में कार्यों की स्थिति तथा जब कभी अपेक्षित हो शोधक उपाय करने की स्थिति में नहीं था।

**अनुशंसा: प्रशासन द्वारा उपयुक्त विनियम, नियमावली तथा प्रक्रिया को तैयार किए जाने के माध्यम से प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है।**

प.प्र.बो. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति तथा इसके अतिरिक्त अनुशंसा को स्वीकार किया (मई 2015) तथा बताया कि प्रत्येक छः महीने में बोर्ड की बैठकें की जाएंगी।

### 2.1.8 निष्कर्ष:

प.प्र.बो. के उद्देश्यों ने अ.नि.द्वी. के पत्तनों पर पत्तन सुविधाओं के विस्तार, पोत परिवहन प्रबंधन तथा माल के भण्डारण के लिए तथा बन्दरगाहों के रखरखाव हेतु प्रभारों की वसूली तथा संग्रहण के प्रति नियमों एवं विनियमों के निरूपण को आवश्यक बनाया। तथापि, उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अपेक्षित शक्तियों से बोर्ड निहित नहीं था। प.प्र.बो. द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्यों के सुचारु रूप में संचालन हेतु आवश्यक आवधिक नियमों एवं विनियमों को तैयार करने के लिए प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई थी। इस प्रकार, जलयान/ कार्गो संबंधित सेवाओं हेतु प्रभारों की वसूली तथा संग्रहण में कमियां थीं, कार्गो प्रबंधन हेतु कार्यबल को दक्षता से नियंत्रित नहीं किया गया था; राजस्व के संवर्धन हेतु कोई नीति नहीं थी और न ही भूमि प्रबंधन हेतु कोई नीति तैयार की गई थी। उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अभाव ने प.प्र.बो. के कार्यों को और भी प्रभावित किया था। प.प्र.बो. ने लेखापरीक्षा की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार किया। तथापि, अ.नि.द्वी. प्रशासन ने रिपोर्ट (मार्च 2015) दिए जाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी (जून 2015)। इसे गृह मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया गया था (मार्च 2015)। उनका उत्तर भी जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

### अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

#### सचिवालय, पोर्ट ब्लेयर

### 2.2 एक परियोजना को प्रारम्भ करने में अनुचित विलम्ब

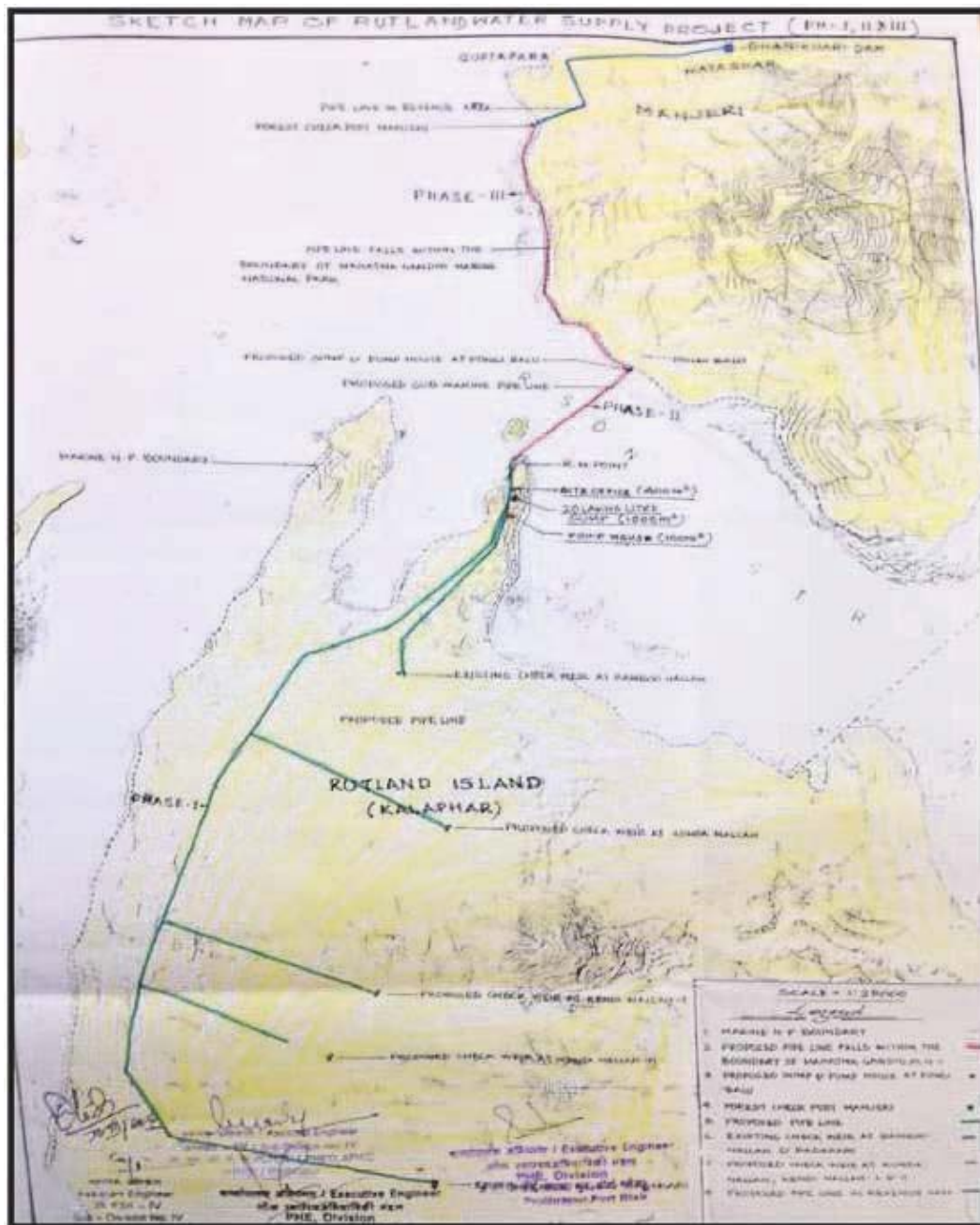
पोर्ट ब्लेयर में पेयजल के भारी संकट की जिसकी 2007 में कल्पना की गई थी, परियोजना के चरण-II हेतु निविदाओं के बार-बार रद्द के कारण इसे कम नहीं किया जा सका। 2011 में ₹13.75 करोड़ की लागत पर परियोजना के चरण-I तथा चरण-III में सृजित अवसरचना का वर्ष में एक या दो महीने के लिए अल्प रूप से उपयोग किया गया था।

पोर्ट ब्लेयर में पेयजल के भारी संकट को कम करने के लिए, अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन (प्रशासन) ने जून 2007 में रूटलैंड द्वीप से पोर्ट ब्लेयर तक जल के परिवहन हेतु एक परियोजना संकल्पित की थी। अण्डमान लोक निर्माण विभाग (अ.लो.नि.वि.) ने तीन चरणों में परियोजना के निष्पादन हेतु एक प्रारम्भिक योजना तैयार की जिसमें निम्न शामिल था:

- i. रूटलैंड द्वीप में पाईपलाईनों का डाला जाना जो सभी नालों को वीयर/चैक डेमो की अपेक्षित संख्या से जोड़ेगी (चरण-I) ;
- ii. रूटलैंड द्वीप में आर.एम.स्थल से दक्षिण अण्डमान द्वीप (पोर्ट ब्लेयर) में पोंगी बालू तक समुद्री पाईपालाईनों का डाला जाना (चरण-II) तथा ;
- iii. पोंगी बालू (चिदयाटापू के पास) से धानीकारी बांध (दक्षिण अण्डमान द्वीप) तक पाईपलाईनों का डाला जाना (चरण-III)।

तीन चरणों के रेखाचित्री नक्शे को मानचित्र 'क' में भी दर्शाया गया है:

मानचित्र-2



### रूटलैंड जल आपूर्ति परियोजना का रेखाचित्री नक्शा

तीन चरणों में परियोजना के निष्पादन को जुलाई 2007 में मुख्य सचिव तथा माननीय उप राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया गया था। परियोजना के चरण-I तथा चरण-III अ.लो.नि. वि. द्वारा निष्पादित किए जाने थे। चरण-II के निष्पादन हेतु राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चैन्नई (रा.म.प्रौ.सं.) से सिफारिश की गई थी। रा.म.प्रौ.सं. ने सितंबर 2007 में

₹13.89 करोड़ की अनुमानित लागत पर चरण-II के निष्पादन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। रा.म.प्रौ.सं. को जमा कार्य के रूप में परियोजना के चरण-II को सौंपे जाने हेतु आवश्यक स्वीकृति की अक्टूबर 2007 में गृह मंत्रालय (गृ.मं.) से माँग की गई थी। गृ.मं. ने बदले में नवम्बर 2007 में शहरी विकास मंत्रालय (श.वि.मं.) से सिफारिश की थी।

श.वि.मं., गृ.मं. तथा प्रशासन के बीच कई पत्राचारों के पश्चात अंत में श.वि.मं. द्वारा अनुसूचित समय अवधि के भीतर समय समाप्त करने के तथा बिना समय/लागत वृद्धि के अनुबन्ध के साथ एक वर्ष से अधिक के पश्चात दिसंबर 2008 तथा जनवरी 2009 में क्रमशः तकनीकी संस्वीकृति तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। परिणामस्वरूप, गृ.मं. ने ₹13.89 करोड़ के कुल परिव्यय सहित रूटलैंड द्वीप से दक्षिण अण्डमान द्वीप तक समुद्री पाईपलाईनों को डाले जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। रा.म.प्रौ.सं. ने कार्य निष्पादन को अस्वीकार किया तथा अनुमानित लागत को ₹13.89 करोड़ से ₹18.89 करोड़ तक बढ़ाते हुए अनुमान दो वर्ष पुराना होने तथा पुल के ऊपर से पाईपलाईन डाले जाने के विकल्प को शामिल किए जाने, जो पिछले अनुमान में नहीं था, के कारण भी जुलाई 2009 में एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

रा.म.प्रौ.सं. के साथ विचार-विमर्शों के पश्चात प्रशासन ने तकनीकी सहायता हेतु रा.म.प्रौ.सं. की नियुक्ति के साथ निविदा आमंत्रित करने का निर्णय किया (नवम्बर 2010)। तथापि, प्रशासन ने तकनीकी परामर्श कार्य हेतु रा.म.प्रौ.सं. के साथ कोई करार नहीं किया। रु.अ.<sup>23</sup> दिसंबर 2010 में आमंत्रित की गई थीं परंतु उन्हें विज्ञापित रु.अ. में कुछ विशिष्ट नियमों एवं शर्तों की कमी के कारण निर्माणकार्य सलाहकार बोर्ड (नि.स.बो.) के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे प्रशासन के मुख्य सचिव के आदेश पर मार्च 2011 में रद्द कर दिया गया था। यह इस तथ्य के बावजूद किया गया कि रु.अ. का नि.स.बो. के तकनीकी कार्मिकों द्वारा उचित रूप से पुनर्निरीक्षण किया गया था तथा इसे विज्ञापित किए जाने से पूर्व मुख्य सचिव द्वारा अंततः अनुसमर्थित किया गया था। संशोधन के पश्चात, जून 2011 में फिर से रु.अ. आमंत्रित की गई थीं। बोलियों का अंतिम मूल्यांकन रा.म.प्रौ.सं. से एक विशेषज्ञ सदस्य की उपस्थिति में नि.स.बो. की बैठक (जनवरी 2012) में किया गया था। समय पर वार्षिक स्फीति दरों को लागू करके लागत के उपयुक्त औचित्य पर ₹28.50 करोड़ की न्यूनतम उद्धरित दर की स्वीकृति हेतु नि.स.बो. द्वारा सिफारिश की गई थी। फिर भी, रु.अ. को माननीय प्रशासक द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया (मई 2012) कि रा.म.प्रौ.सं. ने अव्यवसायिक ढंग से परियोजना का अनुमान लगाया था जबकि रा.म.प्रौ.सं. को उसकी तकनीकी जानकारी हेतु नियुक्त किया गया था। माननीय प्रशासक द्वारा निर्देशित किए जाने पर रु.अ. बूट<sup>24</sup> आधार पर आमंत्रित (मई 2012) की गई थी।

<sup>23</sup> रुचि की अभिव्यक्तियां

<sup>24</sup> निर्माण-स्वामित्व-संचालन-अंतरण

बातचीत (मई 2013) के पश्चात, न्यूनतम बोलीकर्ता ने 25 वर्षों की अवधि तक 6022.50 करोड़ लीटर जल के परिवहन हेतु 4.10 पैसे प्रति लीटर की दर से बोली लगाई। अ.लो.नि.वि. में 50 वर्षों की जीवन प्रत्याशा तथा बूट प्रणाली के 25 वर्षों के प्रचालन के पश्चात अ.लो.नि.वि. को परिसम्पत्तियों के अंतरण पर विचार करते हुए दर को तर्कसंगत पाया। प्रति लीटर परिवहन लागत को 2012 में जल नौकाओं<sup>25</sup> में रूटलैंड से पोंगी बालू तक जल के परिवहन हेतु किए गए 11.50 पैसे प्रति लीटर के व्यय से भी काफी कम पाया गया।

इस रु.अ. को भी रद्द कर दिया गया था। रद्दीकरण का कारण बूट आधार में निविदा के वित्तीय मूल्यांकन हेतु मानक पद्धति के अभाव को बताया गया। तथापि, संवीक्षा ने उजागर किया कि अ.लो.नि.वि. ने जी.बी. पंत अस्पताल में छूट आधार पर विलवणीकरण संयंत्र, जो दिसंबर 2007 से कार्य कर रहा था, हेतु एक निविदा को अंतिम रूप दिया था।

इस प्रकार, परियोजना के चरण-II कार्य को निविदाओं के बार-बार रद्दीकरण के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका। कार्य की अप्रैल 2015 तक पुनर्निविदा नहीं की गई है। लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना के चरण-I तथा चरण-III अ.लो.नि.वि. द्वारा ₹13.75 करोड़ की कुल लागत पर अक्टूबर 2011 में समाप्त किए गए थे। तथापि, इन पाईपलाइनों का जल के परिवहन हेतु इष्टतम रूप से उपयोग नहीं किया जा सका था क्योंकि रूटलैंड द्वीप में आर.एम. स्थल तथा पोर्ट ब्लेयर में पोंगी बालू के बीच संयोजक समुद्री पाईपलाइनों को नहीं डाला गया था। अ.लो.नि.वि. ने ₹42.64 लाख तथा ₹92.50 लाख व्यय करने के पश्चात रूटलैंड द्वीप तथा पोर्ट ब्लेयर के बीच जल नौकाओं का उपयोग करके क्रमशः मई 2013 में केवल 32300 मीट्रिक टन जल तथा मार्च-मई 2014 में 56400 मीट्रिक टन जल का परिवहन किया था। जल के परिवहन की लागत मई 2013 में 13.20 पैसे प्रति लीटर तथा मार्च-मई 2014 में 16.40 पैसे प्रति लीटर थी जो 4.10 पैसे प्रति लीटर से काफी अधिक थी जिसे बूट पद्धति के अंतर्गत मई 2013 में न्यूनतम बोलीकर्ता द्वारा मान लिया गया था। पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा जल की अपनी मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली से दूसरे दिन केवल आधे घण्टे के लिए पोर्ट ब्लेयर के आवासियों को आपूर्ति भी की जा रही थी।

इस प्रकार, पोर्ट ब्लेयर में चरण-II हेतु निविदाओं के बार-बार रद्द की वजह से परियोजना के अपर्याप्त प्रबंधन के कारण पेयजल के भारी संकट को कम नहीं किया गया था। 2011 में ₹13.75 करोड़ की लागत पर परियोजना के चरण-I तथा चरण-III में सृजित अवसंरचना का वर्ष में एक या दो महीनों में न्यूनतम उपयोग किया गया था।

अ.लो.नि.वि. ने अप्रैल 2015 में पैरा में उल्लिखित तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की थी।

मामला फरवरी 2015 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतिक्रियित था।

<sup>25</sup> एक लंबी सपाट तल वाली नौका

## जिला परिषद, दक्षिण अंडमान, पोर्ट ब्लेयर

### 2.3 निष्फल व्यय

अक्टूबर 2004 में निर्माण हेतु संस्वीकृत दाहगृह को एक ही प्रशासन के दो विभागों में समन्वय की कमी तथा जिला परिषद के निरूत्साही दृष्टिकोण के कारण दस वर्षों से अधिक के विलंब के बाद भी परिचालनात्मक नहीं किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप ₹73.95 लाख का निष्फल व्यय हुआ था।

जिला परिषद, दक्षिण अण्डमान (जि.प.) ने गाराचरमा में एल.पी.जी.<sup>26</sup> वाले दाहगृह के निर्माण हेतु प्रस्ताव को संस्वीकृत किया था (अक्टूबर 2004)। तदनुसार, अध्यक्ष, जि.पं. ने अक्टूबर 2006 में ₹55.60 लाख की लागत पर एल.पी.जी. वाले शमशान के निर्माण हेतु प्रशासनिक अनुमति तथा व्यय संस्वीकृति दी थी।

शमशान के निर्माण का कार्य अप्रैल 2008 में पूरा करने की निर्धारित तिथि के साथ अप्रैल 2007 में एक फर्म को दिया गया था। फर्म ने शमशान का निर्माण कार्य सितम्बर 2010 में किया था तथा उसे अक्टूबर 2014 तक ₹72.89 लाख का भुगतान किया गया था।

अभिलेख से प्रकट हुआ कि यद्यपि शमशान एल.पी.जी. वाला था, नियंत्रण पैनल, तापमान नियंत्रण प्रणाली, वैचुरी प्रणाली के साथ धौकनी आदि जैसे विभिन्न विद्युत घटकों के परिचालन हेतु तीन चरण के विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता थी। इसलिए, शमशान के पूरा होने के पश्चात् ग्राम पंचायत (गाराचरमा-II) ने विद्युत विभाग (वि.वि.), अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन से शमशान भवन को तीन चरण के विद्युत कनेक्शन को प्रदान करने के लिए निवेदन किया (सितम्बर 2010) तथा इसका अनुसरण जि.पं. द्वारा जनवरी 2011 में किया गया था। चूंकि वि.वि. द्वारा कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी, जि.पं. ने अपने पूर्व निवेदन के 18 माह पश्चात् फिर से वि.वि. से शीघ्रतिशीघ्र विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए कहा था (जुलाई 2012)। शमशान वि.वि. के प्रोथरापुर उप-प्रभाग के अधिकार क्षेत्र में स्थित था। सितम्बर 2012 में प्रोथरापुर उप-प्रभाग ने उप-प्रभाग की सूचना के अंतर्गत अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय), वि.वि. के पक्ष में राशि को जमा करने का निवेदन करते हुए ₹1.06 लाख की माँग रखी थी। जनवरी 2013 में अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय) के पास राशि जमा करवाते समय जि.पं. बिजली का कनेक्शन प्रदान करने के लिए संबंधित उप-प्रभाग को सूचित करने में विफल रहा। जि.पं. ने मामले का अनुसरण अगले 15 महीनों तक नहीं किया तथा केवल मई 2014 में वि.वि. को केवल अनुस्मारक भेजा था।

जि.पं. द्वारा किए गए भुगतान से अनभिज्ञ, प्रोथरापुर उप-प्रभाग ने जि.प. को फिर से राशि जमा करने के लिए कहा (मई 2014)। परिणामस्वरूप, जि.पं. ने प्रोथरापुर उप-प्रभाग को सूचित करते हुए अधिशाषी अभियंता (मुख्यालय), वि.वि. के समक्ष मुद्दा उठाया। तथापि,

<sup>26</sup> लीक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस

अधिकासी अभियंता (मुख्यालय), वि.वि. से प्रोथ्रापुर उप-प्रभाग द्वारा भुगतान के विवरण अक्टूबर 2014 से ही प्राप्त किए गए थे। तीन चरण का कनेक्शन जनवरी 2015 में शमशान भवन को प्रदान कर दिया गया था परंतु वि.वि. द्वारा यह पाया गया था कि दाहगृह भवन में आवश्यक वायरिंग नहीं की गई थी। वि.वि. ने जि.पं. से कनेक्शन हेतु अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का निवेदन किया था (मार्च 2015) जो प्रस्तुत नहीं किया गया था (मई 2015)।

अक्टूबर 2004 में निर्माण हेतु स्वीकृत दाहगृह कुछ छोटे मुद्दों का निपटान न किए जाने के कारण ₹73.95 लाख का व्यय करने के बावजूद भी दस वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी चालू नहीं हुआ था। यह जिला परिषद की ओर से निष्क्रियता तथा एक ही प्रशासन के दो विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण था जिसका परिणाम निष्फल व्यय के रूप में हुआ। यह प्रशासन द्वारा मॉनीटरिंग की अनुपस्थिति के बारे में चिंता व्यक्त करता है।

मामले को नवम्बर 2014 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतिक्षित था।

## संघ शासित क्षेत्र, दादरा एवं नागर हवेली, ग्रामीण विकास विभाग

### 2.4 ₹317.03 लाख का व्यर्थ व्यय

लो.नि.वि. विभाग, ने संघ शासित क्षेत्र, दादरा एवं नागर हवेली, ने पाईप लाईन नेटवर्क में पाईपों की उन विशिष्टताओं का पालन नहीं किया था, जिसकी बैपकोस, एक सलाहकार, द्वारा सिफारिश की गई थी, जिसका परिणाम ₹317.03 लाख के व्यर्थ व्यय में हुआ।

लोक निर्माण विभाग, संघ शासित क्षेत्र दादरा एवं नागर हवेली की जिला पंचायत ने मैसर्स वाटर एण्ड पावर कंसलटेंसी सर्विसेस (इण्डिया), लि. (वैपकोस) को मंडोनी में जल आपूर्ति हेतु विभिन्न संरचनाओं के आर.सी.सी. डिजाईन, पम्पिंग मशीनरी के हाईड्रोलिक डिजाईन तथा पाईप नेटवर्क प्रणाली सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक सलाहकार के रूप में नियुक्त (जून 1999) किया था. वैपकोस ने ₹8.84 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ पाईप डिजाईनिंग तथा स्थलों के चयन सहित अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की (दिसम्बर 2000)। डी.पी.आर. में, यह सिफारिश की गई थी कि संवितरण नेटवर्क में ढलवां लोहा (सी.आई.) पाईप का उपयोग किया जाना चाहिए। दो भागों की बनी परियोजना को सितम्बर 2007 में पूर्ण किया जाना निर्धारित था:

भाग 1— भूमिगत हौदी तक जल उपचार संयंत्र में दमन गंगा नदी से वासडा हैदवाचिमल तक कच्चा जल पाईप लाईन



भाग 2— हौदी से क्षेत्र I, II तथा III (आई.एस.आई. चिन्हित सी.आई.एस./ एस. पाईप लाईने) तक स्वच्छ जल का संवितरण नेटवर्क

जिला पंचायत (जि.पं.) ने भाग-1 एवं 2 हेतु निधियों की उपलब्धता के बावजूद केवल भाग 2 कार्य को पहले करने का निर्णय लिया तथा कार्य को सितम्बर 2007 को समापन की निर्धारित तिथि सहित ₹317.03 लाख की लागत पर चार<sup>27</sup> विभिन्न दलों को सौंपा (फरवरी 2007) गया था जिसे अंततः समय सीमा के भीतर पूर्ण किया गया था। 2011 में भाग 1 कार्य करने का निर्णय लिया गया था। परियोजना को केवल भाग 1 को भाग 2 से जोड़े जाने के पश्चात ही पूर्ण माना जाना था क्योंकि स्वच्छ जल को पहले से पूर्ण तथा संस्थापित पाईप लाईन नेटवर्क को जोड़कर ही संवितरित किया जा सकता था।

भाग 1 को भाग 2 के साथ जोड़ने के लिए विभाग द्वारा मैसर्स फैंसाईल मावेन प्रा.लि. के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया था (फरवरी 2013) जिन्होंने सूचित किया था कि नेटवर्क ढलवा लोहा (सी.आई.) पाईपों के स्थान पर कलईदार लोहा (जी.आई.) पाईपों के साथ डाला गया था। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट ने यह भी प्रकट किया कि पाईपों के व्यास में बदलाव, दबाव मुक्त प्रणाली तथा भारी तरंगी भू-प्रोफाईल की गैर-स्थापना के कारण जी.आई. पाईपों की मौजूदा प्रणाली उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही थीं तथा इन्हें सी.आई. पाईपों के साथ बदला जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि भाग 2 (क्षेत्र I,II,III एवं हौदी) के कार्य की तकनीकी संस्वीकृति अधीक्षक अभियंता, सं.शा.क्षे. दा.एवं न.ह. द्वारा प्रदान की गई थी। तकनीकी संस्वीकृति प्रदान करते समय वैपकोस द्वारा प्रदान की गई डिजाईन विशिष्टताओं का अनुसरण नहीं किया गया था तथा परिणामस्वरूप भाग 2 का पूर्ण पाईप लाइन नेटवर्क अनुपयोगी पाया गया था। विभाग को क्षेत्र I,II एवं III के संवितरण पाईपलाईन नेटवर्क के कार्य को नए सिरे से करना पड़ा। लेखापरीक्षा ने पाया कि दूसरे चरण के कार्य के लिए अक्टूबर 2014 में फिर से नई निविदाएं की गई थीं तथा एक फर्म द्वारा ₹830.98 लाख की प्रस्तावित न्यूनतम निविदा को स्वीकार किया गया था। इस प्रकार, भाग 2 के अंतर्गत पहले डाले गए पाईपो पर किया गया ₹317.03 लाख का व्यय व्यर्थ साबित हुआ तथा परियोजना की लागत भी ₹513.95 लाख तक बढ़ी।

उपर्युक्त तथ्यों को कार्यकारी अभियंता द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसने बताया कि विशिष्टताओं को प्रारम्भ में वैपकोस द्वारा डिजाईन किया गया था परंतु लो.नि.वि. द्वारा उनकी अनुपालना नहीं की गई थीं तथा ऐसे विचलन हेतु विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की गई हो भी नहीं पाया गया था।

इस प्रकार, परियोजना की तकनीकी संस्वीकृति तैयार करते समय सलाहकार अभिकरण

<sup>27</sup> मेसर्स के.के. राठोड़ (₹83.37 लाख) (2) मेसर्स यूनिटी इन्टरप्राईजेज (₹84.31 लाख) (3) मेसर्स उमिया विलय कंस्ट्रक्शन (₹97.44 लाख) (4) टी.बी. परमार (₹51.92 लाख)

द्वारा अनुशंसित विशिष्टताओं की अनुपालना करने में विभाग की विफलता का परिणाम ₹317.03 लाख के व्यर्थ व्यय के रूप में हुआ। आगे दो गैर-समकालिक चरणों में कार्य को प्रारम्भ करने के कारण भाग 2 के कार्य निष्पादन में विचलन का पता छः वर्ष बाद लगाया जा सका एवं इसमें सुधार हुआ था। इस कारण, उसी कार्य हेतु ₹513.95 लाख का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

मामला प्रशासक तथा मंत्रालय को क्रमशः मार्च 2015 तथा मई 2015 में प्रेषित किया गया था, उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

### संघ शासित क्षेत्र, दमन एवं दीव, पर्यटन विभाग

#### 2.5 बजट अनुदान की समाप्ति से बचने के लिए ₹5.50 करोड़ का अनियमित आहरण

संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, दमन ने बजट अनुदान की समाप्ति से बचने के लिए मार्च 2012 में ₹5.50 करोड़ की एक परियोजना, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मार्च 2014 में स्वीकृत किया गया था के लिए ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम के पास अनियमित रूप से रखा।

प्राप्ति एवं भुगतान नियमावली, 1983 के नियम 100 का उपनियम 2 अनुबंध करता है कि सरकारी खाते से किसी भी धन का आहरण नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी तुरंत संवितरण हेतु आवश्यकता न हो। माँगों की प्रत्याशा में अथवा बजट अनुदान की समाप्ति से बचने हेतु सरकारी खातों से धन का आहरण स्वीकार्य नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पर्यटन विभाग, दमन ने जमपूर समुद्र तट पर सी.एच. 350 मीटर से 1850 मीटर की सुरक्षा दीवार (समुद्र अपरदन) के निर्माण के कार्य हेतु ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम (ओ.आई.डी.सी.) के पास मार्च 2012 में ₹5.50 करोड़ जमा किए। ओ.आई.डी.सी. के पास निधियों को जमा करने के समय सक्षम प्राधिकारी की न तो प्रशासनिक स्वीकृति अथवा व्यय संस्वीकृति थी और न ही तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त की गई थी। आगे लेखापरीक्षा ने पाया कि इन कार्य हेतु दिसम्बर 2013 में ओ.आई.डी.सी. के मुख्य अभियंता द्वारा ₹33.09 करोड़ की राशि की तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की गई थी। ₹5.50 करोड़ के जमा को पूर्ण कार्य हेतु प्रारंभिक जमा के रूप में माना गया था। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त परियोजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति सं.शा.क्षे. की स्थायी वित्त समिति (प्रशासक, विकास आयुक्त तथा वित्त सचिव को शामिल कर के बनी) द्वारा मार्च 2014 में प्रदान की गई थी। इसलिए, मार्च 2012 में ओ.आई.डी.सी., दमन के पास ₹5.50 करोड़ के जमा के समय न तो कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट थी और न ही अपेक्षित संस्वीकृतियां प्राप्त की गई थीं। ओ.आई.डी.सी. में अभिलेखों की संवीक्षा ने यह भी प्रकट किया कि कथित कार्य हेतु निविदा को भी ओ.आई.डी.सी. द्वारा (दिसम्बर 2014 तक) अंतिम रूप भी नहीं दिया गया था तथा तब तक कोई व्यय भी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, मार्च 2012 के महीने में सरकारी खातों से आहरित तथा ओ.आई.डी.सी. के पास जमा किए गए ₹ 5.50 करोड़ की राशि कार्य हेतु तुरंत संवितरण के लिए नहीं थी बल्कि इसका आहरण बजट अनुदान की समाप्ति से बचने के लिए किया गया था जो अनियमित था।

मामला मई 2015 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; इसका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

## केन्द्र शासित क्षेत्र, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली, पुलिस विभाग

### 2.6 संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण न किया जाना

पुलिस विभाग के लिए संचार नेटवर्क के लिए टेट्रा तकनीक के कार्यान्वयन में सं.शा.क्षे. प्रशासन विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण नहीं हुआ। तटीय एवं संवेदनशील सं.शा.क्षे. में आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत यह प्रणाली जरूरी एवं महत्वपूर्ण गतिविधि है। सं.शा.क्षे. प्रशासन ने भी चार वर्षों से अधिक से ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम (ओ.आई.डी.सी.) के पास ₹484.38 लाख की निधि को अवरुद्ध भी किया।

संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस बल की परिचालनात्मक क्षमता के सशक्तिकरण तथा अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाने की दृष्टि से गृह मंत्रालय (गृ.मं.) ने दिल्ली के रा.रा.क्षे., चण्डीगढ़, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली, पांडिचेरी, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप हेतु पुलिस आधुनिकीकरण योजना (पु.आ.यो.) को शुरू करने के लिए अप्रैल 2006 में ₹884 करोड़ संस्वीकृति किए थे। पु.आ.यो. की अवधि 2006-07 से शुरू होकर 2010-11 तक की थी जिसे कि 2012-13 तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दमन एवं दीव के संघ शासित क्षेत्र ने संचार, उपकरण, वाहनों, पुलिस स्टेशन/इमारतों, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हथियार आदि जैसे विभिन्न घटकों पर पु.आ.यो. के अंतर्गत पाँच वर्षों की अवधि में ₹22.50 करोड़ संस्वीकृत किया था। वर्ष 2007-08 के लिए कार्रवाई योजना की समिति ने निर्णय लिया (जनवरी 2008) कि एक परियोजना के रूप में दोनों संघ शासित क्षेत्रों (दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली) को शामिल करते हुए एक समग्र रेडियो वायरलेस प्रणाली को स्थापित किया जाए। परियोजना का उद्देश्य संचार नेटवर्क को सशक्त करना तथा पुलिस माहौल में सुधार लाना था। परियोजना की अनुमानित लागत ₹500 लाख थी (दादरा एवं नागर हवेली के लिए ₹200 लाख तथा दमन एवं दीव के लिए ₹300 लाख)।

मेसर्स टैली संचार परामर्शदाता इंडिया लिमिटेड, (टै.सं.प.इं.लि.) को तकनीकी परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था (मई 2009)। टै.सं.प.इं.लि. ने तकनीकी सर्वेक्षण का संचालन किया तथा वायरलेस रेडियो ट्रैकिंग वायरलेस प्रणाली के लिए टैट्रा तकनीक की सलाह दी थी। टै.सं.प.इं.लि. को परामर्शदाता शुल्क के रूप में ₹12.40 लाख का भुगतान किया गया था।

दमन एवं दीव के पुलिस विभाग ने मल्टीसाइट यू.एच.एफ. डिजिटल ट्रंकिंग प्रणाली (टैट्रा) के कार्यान्वयन हेतु निविदाएं जारी की थी और चार बोलीदाताओं अर्थात् (I) एच.सी.एल (II) 3 जी वायरलैस संचार (III) टैक महिन्द्रा एवं (IV) मोटोरोला इंडिया ने बोली लगाई थी। तकनीकी बोली 23.03.2009 को खोली गई थी। तकनीकी समिति द्वारा यथोचित विमर्श के पश्चात् समिति ने उपरोक्त चार बोलीदाताओं से मूल्य की बोली आमंत्रित की थी। बाद में केन्द्रीय सतर्कता आयोग (के.स.आ.) ने परियोजना के बोली के दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान कमियां पाई तथा उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया था। क्रय समिति द्वारा (परामर्शदाता की अनुसंधान पर) मौजूदा निविदा को रद्द करके परियोजना हेतु एक नई निविदा को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया (नवम्बर, 2009) था।

इसी बीच में, परियोजना के पूर्ण होने के लिए बिना कोई समय सीमा निर्धारित किए तथा संदर्भ की शर्तों के बिना टैट्रा प्रणाली के हेतु 03.02.2010 को ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम (ओ.ओ.वि.नि.) लिमिटेड, दमन नोडल अभिकरण के रूप में नियुक्त किया था। पुलिस विभाग ने परियोजना लागत के प्रति ओ.ओ.वि.नि. लिमि. के पास 04 फरवरी 2010 को ₹397.72 लाख तथा 12 मई 2010 को ₹86.66 लाख जमा किया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए ओ.ओ.वि.नि. तथा पुलिस विभाग द्वारा आगे की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पु.आ. यो. (सं.शा.क्षे.) गृ.मं हेतु उच्च अधिकार प्राप्त समिति की 14 मार्च 2012 को हुई बैठक में यह उल्लिखित किया गया था कि 2012-13 पु.आ.यो. के लिए अंतिम वित्तीय वर्ष था तथा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए जहां संबंधित सं.शा.क्षे. वर्ष 2012-13 में निविदा गतिविधियों को पूरा करने तथा क्रय आदेश को अंतिम रूप देने में आश्वस्त नहीं था। गृ. मं. ने मई 2013 में भी पिछले वित्त वर्षों 2008-12 (2012-13 को छोड़कर) से संबंधित निधियों के पुनर्विनियोग/पुनर्वैधीकरण हेतु आई.जी.पी. दमन एवं डी. एवं एन.एच के अनुरोध को टुकराया था तथा पिछले वित्त वर्षों के शेष का अभ्यर्पण करने का निर्देश दिया था। यह पाया गया था कि ₹478.86 लाख के अव्ययित निधियों का अभ्यर्पण पुलिस विभाग ने गृ.मं. को जुलाई 2014 तक नहीं किया था। जुलाई 2014 में, ओ.ओ.वि.नि. ने दा.एवं ना.ह. के सं.शा.क्षे. से संबंधित ₹188.55 लाख की राशि की वापसी की थी जिसका अभ्यर्पण सं.शा. क्षे. प्रशासन द्वारा गृ.मं. को दिसम्बर 2014 में किया गया था। दमन एवं दीव के सं.शा.क्षे. से संबंधित ₹290.31 लाख तक की राशि की निधियां अभी भी ओ.ओ.वि.नि. लिमिटेड के पास पड़ी हुई थी (अप्रैल 2015)।

इस प्रकार, सं.शा.क्षे. प्रशासन द्वारा की गई सुस्त कार्रवाई का परिणाम दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली के पुलिस विभाग के लिए संचार नेटवर्क हेतु टैट्रा तकनीक के गैर-कार्यान्वयन में हुआ तथा चार वर्षों से अधिक के लिए ₹484.38 लाख की निधियों के अवरोधन में भी हुआ। यद्यपि, दा.ना.ह. के सं.शा.क्षे. से संबंधित ₹188.55 लाख की निधियों

की वापसी जुलाई 2014 में ओ.ओ.वि.नि. द्वारा कर दी गई थी, दमन एवं दीव के सं.शा.क्षे. से संबंधित ₹290.31 लाख अभी भी ओ.ओ.वि.नि. के पास पड़ी हुई थी। रेडियो ट्रकिंग वायरलैस प्रणाली के तटीय तथा संवेदनशील संघ शासित क्षेत्रों में संस्थापन के उद्देश्य की भी प्राप्ति नहीं हो पाई थी। अभ्यास निष्फल रहा।

इसे क्रमशः मार्च 2014 तथा नवम्बर 2014 में सं.शा.क्षे. प्रशासन तथा गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

### संघ शासित क्षेत्र, दमन एवं दीव, पर्यटन विभाग

#### 2.7 लेखापरीक्षा दृष्टांत पर वसूली

लोक निर्माण विभाग, दमन ने दिसंबर 2006 में एक कार्य हेतु कुल ₹200.00 लाख की निधियों का अनियमित रूप से आहरण किया था तथा उसे ओम्निबस औद्योगिक विकास निगम (ओ.ओ.वि.नि.) के पास जमा कराया था। कार्य प्रारम्भ नहीं किया था तथा राशि आठ वर्षों से अधिक तक (दिसम्बर 2014 तक) ओ.ओ.वि.नि. के पास पड़ी थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर ओ.ओ.वि.नि. द्वारा राशि को वापस किया गया था (मार्च 2015)।

केन्द्रीय खजाना नियमावली का नियम 290 प्रावधान करता है कि “ खजाने से किसी धन का आहरण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह तुरंत संवितरण हेतु अपेक्षित न हो। माँगों के पूर्वानुमान अथवा बजट अनुदानों के व्यपगत होने से बचने हेतु धन का आहरण करना अनुमत नहीं है”

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), दमन तथा ओ.ओ.वि.नि.; दमन के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि लो.नि.वि., दमन ने ओ.ओ.वि.नि. के पास ₹200.00 लाख जमा किए थे जैसा नीचे ब्योरा दिया गया है;

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि	जमा की तिथि	प्राप्त निधियाँ (₹ लाख में)
1.	एम.जी. रोड सहित समुद्र के सामने वाली सड़क का सौंदर्यीकरण	सितंबर 2006	दिसंबर 2006	₹200.00

लेखापरीक्षा ने पाया कि निधि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए बिना जारी की गई थी। निधि की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी क्योंकि परामर्श/अन्य व्यय के प्रति केवल ₹0.38 लाख का व्यय किया गया था तथा आठ वर्षों के पश्चात भी कोई एन.आई.टी. जारी नहीं की गई थी। कुल ₹199.62 लाख की शेष निधियां ओ.ओ.वि.नि. के पास जमा में पड़ी हुई थीं (दिसंबर 2014)।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर लो.नि.वि., दमन ने बताया (जून 2015) कि निधियों को प्रशासक द्वारा स्वीकृत नोट के अनुसार ओ.ओ.वि.नि. के लिए रखा गया था तथा इसे ओ.ओ.वि.नि. को जमा कराने हेतु कोई विशेष नियम एवं शर्तें अभिलेख पर नहीं थीं। ओ.ओ.वि.नि. को कोई निर्धारित तिथियां नियत नहीं की गईं तथा आज तक ओ.ओ.वि.नि. के साथ कार्य की समाप्ति हेतु कोई पत्राचार नहीं किया गया था। आगे यह बताया गया (जुलाई 2015) कि ओ.ओ.वि.नि. ने लो.नि.वि. के कार्य "समुद्र के सामने वाली सड़क एम.जी.रोड का सौंदर्यीकरण" के पूर्ण जमा के प्रति ₹200.00 लाख की राशि को वापस कर दिया था (मार्च 2015)। ₹200.00 लाख की वापस की गई राशि को लो.नि.वि., दमन द्वारा सरकारी खाते में जमा (मार्च 2015) करा दिया गया था।

इस प्रकार, लो.नि.वि. द्वारा ₹200.00 लाख का अनियमित आहरण आठ वर्षों से अधिक के लिए इसके अवरोध का कारण बना तथा लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अतंतः इसकी वसूली की गई थी तथा सरकारी खाते में जमा कराया गया था।

मामला, मई 2015 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

## संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप

### 2.8 सरकारी निधियों का अनियमित रखा जाना

**लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड (ल.वि.नि.लि.) के पास कुल ₹216.59 करोड़ की निधियों को रखना तथा ₹40.48 करोड़ की अव्ययित राशि को लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र (ल.सं.शा.क्षे.) को अंतरण न करने के परिणामस्वरूप कुल ₹257.07 करोड़ के सरकारी धन का अवरोधन हुआ।**

सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) का नियम 26 अनुबंध करता है कि व्यय उसी के लिए किया जाना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए निधियाँ प्रदान की गई हैं। नियम 30(II) अनुबंध करता है कि जब संस्वीकृति एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधान में से व्यय का प्रावधान करती है तो वह उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। नियम 56 (1 एवं 2) आगे यह भी अनुबंध करता है कि "वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान की गई तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व उपयोग न की गई निधियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त माना जाएगा तथा उपयोग न किए गए प्रावधान का सरकार को अभ्यर्ण किया जाना चाहिए।"

लेखापरीक्षा ने पाया कि लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र (ल.सं.शा.क्षे.) प्रशासन ने प्रत्येक वर्ष के दौरान नए जलयानों के प्रापण हेतु अनुमान तैयार किए तथा भारत सरकार ने नए यात्री जलयानों के अधिग्रहण हेतु पूंजीगत परिव्यय के रूप में बजटीय आवंटन के माध्यम से ल.सं.शा.क्षे. को निधियां आबंटित की। ल.सं.शा.क्षे. प्रशासन द्वारा प्राप्त की गई निधियों का

संबंधित शिपयार्डों को चरण भुगतान हेतु इसे एक ब्याज वहन करने वाले खाते में रखने के निर्देश के साथ लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड (ल.वि.नि.लि.) को अंतरण किया गया था।

### 2.8.1 निधियों को रखना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2002-03 से 2013-14 की अवधि के लिए ल.वि.नि.लि. (अनुबंध-VIII) को ₹749.70 करोड़ की कुल राशि का अंतरण किया गया था, जिसमें से ल.वि.नि.लि. ने मार्च 2014 तक ग्राहकों को केवल ₹525.92 करोड़ (इसमें 2013-14 में की गई वापसियां शामिल हैं) की राशि जारी की थी तथा ₹223.78 करोड़ की शेष राशि (अनुबंध-VIII) अभी भी उनके पास पड़ी थी। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ₹223.78 करोड़ की राशि में ₹7.19 करोड़ ल.वि.नि.लि. (दिसम्बर 2007) द्वारा विभिन्न उल्लंघनों जैसे कि सुपूदगी में विलम्ब, अपर्याप्त गति, अधिक ईंधन खपत, कुल भार टन भार आदि हेतु विभिन्न शिपयार्डों से परिसमापन क्षति द्वारा प्राप्त किए गए थे। इन्हें ल.वि.नि.लि. के पास रखने के बजाए वसूली पर तुरंत ल.सं.शा.क्षे. को लौटाया जाना था।

विभाग ने तथ्यों एवं आंकड़ों को सुनिश्चित करते समय उत्तर दिया (मार्च 2014) कि धन का निर्गम शिपयार्डों द्वारा कार्य के समापन पर निर्भर है इसलिए व्यय के यथार्थ समय की पहले ही पूर्व सूचना नहीं दी जा सकती तथा शिपयार्डों को भुगतान जारी करने के लिए निधियों को तैयार रखा जाना था। जलयानों की कुल निर्माण लागत के अतिरिक्त ल.वि.नि.लि. के पास कोई अधिक निधि नहीं रखी थी। विभाग ने स्वीकार किया कि ल.वि.नि.लि. से केवल ₹7.19 करोड़ की वापसी बकाया थी।

### 2.8.2 ब्याज राशि का प्रेषण न होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2013-14 की अवधि हेतु ल.वि.नि.लि. के वार्षिक लेखे के अनुसार, ल.वि.नि.लि. द्वारा मार्च 2014 तक प्राप्त ब्याज की कुल राशि ₹33.29 करोड़ थी जिसका अभी भी सरकारी खाते में प्रेषण किया जाना था (अनुबंध-IX) कई मामलों में शेष का पता लगाने हेतु विभाग तथा ल.वि.नि.लि. के बीच जमा एवं शेषों के आंकड़ों का समाधान नहीं किया गया है।

विभाग ने तथ्य तथा आंकड़ों को सुनिश्चित करते समय उत्तर दिया (मार्च 2014) कि निधि का ल.वि.नि.लि. द्वारा सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार सावधि जमा में निवेश किया गया था। ल.वि.नि.लि. ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि विभाग की निधियों को संबंधित विभाग के साथ समाधान की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है तथा बंद की गई परियोजनाओं हेतु ब्याज सहित जमाओं को वापसी करने के कार्य प्रारम्भ कर दिये गये थे।

विभाग के साथ-साथ ल.वि.नि.लि. के उत्तर को निम्नलिखित के दृष्टांत से देखा जाना है:

- (I) भविष्य की माँगों के पूर्वानुमान में सरकारी धन का आहरण जो नियमों के उल्लंघन में बजट अनुदानों की समाप्ति से बचने हेतु वित्तीय वर्ष से अधिक खींची जाए। ल.सं. शा.क्षे. प्रशासन जहाज निर्माण इकाईयों को केवल चरण भुगतान करने तथा तदनुसार निधियों को आहरण करने हेतु उत्तरदायी था।
- (II) अब तक पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियों तथा वसूलियों, चूंकि वह पहले दर्शाते हैं, को संबंधित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत व्यय की कटौती के रूप में लिया जाएगा उसके बिना जहां ऐसी प्राप्तियों को एक विशिष्ट विभाग को लागू आवंटन की नियमावली के अंतर्गत सा.वि.नि. के नियम 94 के अनुसार राजस्व के रूप में लिया जाना है। इस प्रकार, परिसमापन क्षति के प्रति दिसंबर 2007 में उदग्रहण किए तथा वसूले ₹7.19 करोड़ को ल.वि.नि.लि. के पास रखने के बजाए वसूली पर तुरंत ल.सं.शा.क्षे. को लौटाने चाहिए थे।

इस प्रकार, सा.वि.नि. के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ल.वि.नि.लि. के पास कुल ₹216.59 करोड़ की निधि का अप्राधिकृत रखे जाने तथा ल.सं.शा.क्षे. प्रशासन को ₹40.48 करोड़ (₹7.19 करोड़ + ₹33.29 करोड़) की वापसी योग्य राशि का अंतरण न करने का परिणाम कुल ₹257.07 करोड़ के सरकारी धन के अवरोधन में हुआ था। सावधि जमा से कुल ब्याज प्राप्त करने हेतु विकास कार्यों के लिए बनी आधिक्य निधियों को रखा जाना विवेकपूर्ण नहीं था। प्रणाली को सुप्रवाही बनाने तथा ब्याज सहित सभी रखी हुई निधियों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु कार्रवाई की जाए।

मामला अप्रैल 2014 में गृह मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

## 2.9 विशेष भत्ते का अधिक भुगतान

वित्त मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने अपने कर्मचारियों को एक ही समय पर द्वीप विशेष कार्य भत्ता (दूर्वी.वि.का.भ.) के अतिरिक्त दो विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते अर्थात् विशेष क्षतिपूर्ति (दूरवर्ती स्थान) भत्ता (वि.क्ष.दू.स्था.भ.) तथा हार्ड एरिया भत्ता (हा.ए.भ.) अनुमत किए। यह अपने कर्मचारियों को विशेष भत्ते के कारण ₹79.87 लाख के अधिक भुगतान हुआ।

वित्त मंत्रालय ने निकोबार द्वीपसमूहों में तैनात सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2004 से एक विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते के रूप में मूल वेतन के 25 प्रतिशत की दर पर हार्ड एरिया भत्ता (हा.ए.भ.) प्रदान किया। आदेशों के अनुसार, उन स्थानों में जहां एक से अधिक क्षतिपूर्ति भत्ता स्वीकार्य है तो ऐसे स्टेशनों में तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के पास उस भत्ते का चयन करने का विकल्प होगा जो उन्हें अधिक लाभ प्रदान करें।



वित्त मंत्रालय ने अगस्त 2008 में लक्षद्वीप में मिनीकोय में तैनात सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उसी शर्त के साथ 01 सितंबर 2008 से यह भत्ता प्रदान किया। इस विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते को बाद में, जहां कहीं लागू था, 15 प्रतिशत मूल वेतन+एन.पी.ए. की दर पर लक्षद्वीप के फिलतन, एंडरोट, कालपैनी, छैतलब, कादमत, अमिनी तथा बितरा द्वीपों में तैनात सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया (नवम्बर 2011)।

सं.शा.क्षे.ल. में ग्राम (द्वीप) पंचायतों (ग्रा.दी.पं.), सं.शा.क्षे.ल. प्रकाशगृह तथा प्रकाश जहाजों में कार्य कर रहे कर्मचारियों तथा सं.शा.क्षे.ल. में कार्य कर रहे दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र कोची के कर्मचारियों के वेतन बिल पंजिका की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि कर्मचारियों को सरकारी आदेशों के उल्लंघन में द्वीप विशेष कार्य भत्ता (दी.वि.का.भ.) के अतिरिक्त दोनों विशेष क्षतिपूर्ति (दूरवर्ती स्थान) भत्ता (वि.क्ष.दू.स्था.भ.) तथा हार्ड एरिया भत्ता (हा.ए.भ.) प्रदान किए गए थे। मंत्रालय के आदेशों के अनुसार द्वी.वि.का.भ. को या तो वि.झ.दू.स्था.भ. या फिर हा.ए.भ. के साथ प्राप्त किया जा सकता है तथा एस.सी.ए. को सबसे कम होने से अनिवार्य किया जा सकता है। इस प्रकार, कर्मचारियों को किए गए अधिक भुगतान को ₹79.87 लाख परिकल्पित किया गया था **(अनुबंध X)**।

इसे इंगित किए जाने पर (मई 2013), प्रशासन ने मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया। मंत्रालय ने सुस्पष्ट किया (फरवरी 2014) कि कर्मचारी द्वीप विशेष कार्य भत्ते (द्वी.वि.का.भ.) सहित एक साथ वि.क्ष.दू.स्था.भ. तथा हा.ए.भ. प्राप्त नहीं कर सकते तथा वह द्वी.वि.का.भ. सहित या तो वि.क्ष.दू.स्था.भ. या फिर हा.ए.भ. प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्टीकरण की प्राप्ति के पश्चात, वित्त एवं लेखा विभाग, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने सभी विभागाध्यक्षों को अनियमित भुगतान रोकने हेतु निर्देश जारी किया (फरवरी 2014)। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालयों के निर्देशों के आधार पर, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने संबंधित सभी आ.सं.अ. को सितंबर 2014 से आगे के वेतन बिलों से सितंबर 2008 से मार्च 2014 तक किए गए अधिक भुगतानों की वसूली शुरू करने का निर्देश देते हुए एक कार्यालय ज्ञापन (सितंबर 2014) जारी किया।

मंत्रालय (मार्च 2015) ने सं.शा.क्षे.ल. के उत्तर (अक्टूबर 2014) को भी समर्थित किया कि सं.शा.क्षे.ल. के अंतर्गत आ.सं.अ. को द्वीप विशेष कार्य भत्ता (द्वी.वि.का.भ.) सहित एक साथ हार्ड एरिया भत्ता (हा.ए.भ.) तथा विशेष क्षतिपूर्ति (दूरवर्ती स्थान) भत्ता (वि.क्ष.दू.स्था.भ.) के प्रति अनियमित रूप से प्राप्त अधिक राशि की वसूली शुरू करने हेतु आवश्यक अनुदेश सूचित किया गया था।

इस प्रकार, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन द्वारा वित्त मंत्रालय के का.ज्ञा. (मार्च 2004 तथा अगस्त 2008) में दी गई शर्तों के गैर-अनुपालन का परिणाम ₹79.87 लाख के अधिक भुगतान में हुआ। इस राशि की वसूली प्रतीक्षित थी।

## 2.10 इंसीनरेटर्स के प्रापण एवं संस्थापन में विलंब

सं.शा.क्षे. लक्षद्वीप के प्रशासन द्वारा उचित निधियां होने के बावजूद इंसीनरेटर्स के प्रापण एवं संस्थापन में विलंब के कारणवश 4 वर्षों से अधिक के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के पास ₹39.48 लाख अवरुद्ध हुए तथा अन्य उद्देश्य हेतु ₹23.45 लाख की निधियों का विपथन हुआ था।

2014 की भा.नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 25 में यह उल्लेख किया गया था कि चिकित्सकीय गतिविधियों का अपशिष्ट खतरनाक, जहरीला तथा जानलेवा भी होता है। जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन को सूचित करते समय लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित अस्पतालों में अनिवार्य प्राधिकरण के बिना ही सरकारी अस्पताल जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को बना रहे थे, एकत्रित कर रहे थे तथा निपटान कर रहे थे। जैव चिकित्सा अपशिष्ट की अभिक्रिया तथा निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) को अनुसूची 1, के अनुसार किया जाना चाहिए जिसमें बताया गया है कि मानव शरीर के अपशिष्ट का निपटान या तो इंसीनरेटर्स या फिर गहराई में दफना कर किया जाना चाहिए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय, कवारत्ती की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि मार्च/नवम्बर 2010 में आठ इंसीनरेटर्स के प्रापण के लिए मिशन निदेशक, रा.ग्रा. स्वा.मि. को ₹89.90 लाख दिए गए थे जिसमें से ₹23.45 लाख की राशि को विभाग द्वारा सा.वि.नि. के नियम 26 के उल्लंघन में अन्य उद्देश्यों के लिए विपथित किया गया था। विभाग पर्यावरण के मानदंडों के अनुसार जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान के उद्देश्य की पूर्ति के बिना 4 वर्षों से अधिक हेतु ₹39.48 लाख के शेष को छोड़कर केवल ₹26.97 लाख का उपयोग कर पाया था। मामले को विस्तृत रूप से नीचे दिया गया है:

पर्यावरण की दृष्टि से इंसीनरेटर के संस्थापन हेतु आवश्यकता को समझते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (विभाग) निदेशालय, कवारत्ती ने ₹38.80 लाख की कुल राशि पर अमिनी, अंद्रोथ एवं अगात्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सरकारी अस्पताल, मिनीकोय में प्रत्येक में संस्थापन हेतु 10 कि.ग्रा. प्रति घंटा की क्षमता वाले चार इंसीनरेटर्स के प्रापण हेतु मैसर्स एस्को इंजीनियरिंग प्रा. लिमि, कोलकाता को आपूर्ति आदेश दिया (फरवरी 2010)। आपूर्ति की देय तिथि 20 मार्च 2010 थी जिसे जून 2010 तक आगे बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि विभाग ने मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निदेशालय, राज्य स्वास्थ्य संस्था, कवारत्ती को इंसीनरेटर्स का प्रापण करने तथा संस्थापित करने तथा सहमत नियम एवं शर्तों के अनुसार भुगतान करने के लिए प्राधिकृत करते हुए ₹41 लाख जारी किए गए थे (17 मार्च 2010)।

फर्म मैसर्स एस्को इंजीनियरिंग प्रा.लिमि., कोलकाता द्वारा एक वर्ष के विलंब के पश्चात प्रथम इंसीनरेटर की आपूर्ति (जुलाई 2010) तथा संस्थापना (अप्रैल 2011) मिनीकोय के सरकारी

अस्पताल में की गई थी। वह शेष तीन इंसीनरेटरों की आपूर्ति देय तिथि तक करने में विफल रहे। इसलिए विभाग ने आदेश को रद्द करने का निर्णय लिया (अगस्त 2010)।

इसी दौरान, अगस्त 2010 में सं.शा.क्षे. प्रशासन ने कपलेनी, कदामत, किलतान एवं चेतलात द्वीपसमूहों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्थापन हेतु चार और इंसीनरेटरों के प्रापण हेतु दूसरे सबसे कम बोली लगाने वाले बोलीदाता मैसर्ज एसेप्टिक सिस्टमस कोयम्बटूर को आपूर्ति आदेश जारी किया था। इन चार अतिरिक्त इंसीनरेटरों के लिए रा.ग्रा.स्वा.मि. को ₹48.90 लाख की राशि जारी की गई थी (नवम्बर 2010)। लेखापरीक्षा ने पाया कि मैसर्ज एसेप्टिक सिस्टमस द्वारा 2011 में आपूर्ति किए गए चार इंसीनरेटरों में से तीन तो आपूर्ति आदेश के अनुसार कपलेनी, किलतान तथा चेतलात द्वीपसमूह में संस्थापन के लिए थे परंतु वास्तव में अमिनी, अंदोथ तथा अगात्ती द्वीपसमूह में इन्हे आपूर्ति/संस्थापित किया गया था जहाँ पर पूर्व फर्म मैसर्ज एस्को इंजीनियरिंग प्रा.लिमिटेड को इन्हे स्थापित करना था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि इंसीनरेटरों को अंदोथ (मई 2011) तथा अगात्ती (जनवरी 2014) में संस्थापित किया गया था हालांकि, अमिनी तथा कदामत में स्थल को तैयार न रखने के कारण नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रशासन ने इंसीनरेटरों के प्रापण के लिए उपलब्ध शेष निधियों में से ₹23.45 लाख की राशि को एयर कंडीशनर के संस्थापन प्रभारों एवं अल्ट्रा साउंड मशीन के क्रय के लिए विपथित किया था।

इसी प्रकार, मार्च/नवम्बर 2010 में 8 इंसीनरेटरों के प्रापण हेतु मिशन निदेशक, रा.ग्रा.स्वा. मि., राज्य स्वास्थ्य संस्था को ₹89.90 लाख की कुल राशि में से ₹23.45 लाख को प्रशासन द्वारा अन्य उद्देश्य के लिए विपथित किया गया था। पाँच इंसीनरेटरों का प्रापण किया गया था जिसमें से केवल तीन को संस्थापित किया गया था।

विभाग केवल ₹26.97 लाख का उपयोग कर पाया था जिसमें से अभिप्रेत उद्देश्य की आपूर्ति किए बिना चार वर्षों से अधिक के लिए ₹39.48 लाख का शेष अप्रयुक्त रहा **(अनुबंध—XI)।**

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त तथ्यों को इंगित किए जाने पर (जुलाई 2013), विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि बार-बार दिए गए अनुस्मारकों के बावजूद फर्म ने कपलेनी, किलतान एवं चेतलात हेतु इंसीनरेटरों की आपूर्ति नहीं की थी। स्थल को तैयार न रखने को कदामत तथा अमिनी में गैर-संस्थापना का कारण बताया गया था। आगे यह बताया गया था (दिसम्बर 2014) कि सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से ही राशि को राज्य स्वास्थ्य संस्था (रा.स्वा.ग्रा.सं.) के पास रखा गया था तथा उचित स्वीकृति के साथ इसे कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए उपयोग में लाया गया था।

यह उत्तर इंसीनरेटर्स की शीघ्र आपूर्ति एवं संस्थापन को सुनिश्चित करने में प्रशासन की विफलता को स्पष्ट नहीं करता। यह धन का अंतरण करते समय प्रापण हेतु मिशन के साथ किसी अनुबंध को निष्पादित न करने के कारणों को स्पष्ट नहीं करता, जिसके कारणवश चार वर्षों से अधिक के लिए राज्य अभिकरण के पास ₹39.48 लाख अवरूद्ध हुए तथा सा.वि.नि. प्रावधानों के उल्लंघन में अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों का विपथन हुआ था आवश्यक आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं का सृजन किए बिना प्रापण किए जाने के कारणवश चार वर्षों से अधिक के लिए दो इंसीनरेटर व्यर्थ पड़े रहे। जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट के निपटान हेतु पर्यावरण के मानदंडों का अनुसरण करके इंसीनरेटर्स के प्रापण एवं संस्थापन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी।

मामले को गृह मंत्रालय को संप्रेषित किया गया था (जनवरी 2015) उनका उत्तर जून 2015 तक प्रतीक्षित था।

## 2.11 लेखापरीक्षा के उल्लेख करने पर वसूली ₹27 लाख

संघ शासित क्षेत्र, लक्षद्वीप ने गोदाम कार्यालय के निर्माण के प्रति अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित किए बिना जनवरी 2009 तथा अगस्त 2010 के बीच सहकारी समिति को ₹27 लाख की आर्थिक सहायता जारी की थी। कार्य को चार वर्षों से अधिक तक आरम्भ नहीं किया जा सका था। सहकारी समिति ने उद्देश्य, जिसके लिए आर्थिक सहायता जारी की गई थी, को प्राप्त किए बिना जनवरी 2015 में इसे वापस कर दिया था।

लक्षद्वीप सहकारी विपणन संघ (ल.स.वि.सं.) एक पंजीकृत समिति है जो उपभोज्य तथा गैर-उपभोज्य टिकाऊ उत्पादनों के प्रापण तथा लोक संवितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक उपयोगी वस्तुओं के महाद्वीप से सं.शा.क्षे.ल. के द्वीपों तक परिवहन पर लक्षित है। सं.शा.क्षे.ल. में प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा लोक संवितरण हेतु अपेक्षित पूर्ण माल का बैपोर पत्तन के माध्यम से प्रापण तथा प्रेषण किया जाता है। ल.स.वि.सं. बैपोर पत्तन के माध्यम से संचालित माल के एक बड़े भाग को शामिल करता है। इसलिए सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन द्वारा बैपोर पर ल.स.वि.सं. हेतु गोदाम/कार्यालय का निर्माण करने का निर्णय (2009) लिया गया था। प्रशासन ने जनवरी 2009 तथा अगस्त 2010 के बीच छः किशतों में ₹54 लाख (₹27 लाख ऋण तथा ₹27 लाख आर्थिक सहायता) प्रदान किए। आर्थिक सहायता तथा ऋण के कारण राशि को आवेदन तथा ल.स.वि.सं. द्वारा प्रस्तुत कार्यकारी समिति प्रस्ताव/बन्धकपत्र के आधार पर अदा किया जाना था। ऋण समय-समय पर बकाया मूल पर 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर देय ब्याज के साथ मूल की 15 बराबर किशत में प्रतिदेय था। आर्थिक सहायता के भुगतान हेतु आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया था कि राशि का एक वर्ष के भीतर उसी उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना था जिसके लिए

वह संस्वीकृत थी तथा यदि संस्वीकृत राशि का कोई भाग अप्रयुक्त रहता है तो उसे सरकार को वापस लौटाया जाएगा तथा इस संबंध में एक प्रमाणपत्र प्रशासन को प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सं.शा.क्षे. लक्षद्वीप प्रशासन ने बैपौर में ल.स.वि.सं. परिसर में ₹1.35 करोड़ की लागत पर चार गोदामों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति केवल दिसंबर 2010 में जाकर ही प्रदान की थी। इस प्रकार निधियाँ प्र.स्वी. तथा व्य.सं. प्रदान किए जाने से पूर्व जारी की गई थी।

मार्च 2011 में, ल.लो.नि.वि. ने पत्तन विकास क्षेत्र में निर्माण कार्य को निष्पादित करने हेतु अनुमति की माँग करते हुए मामले को पत्तन निदेशक, केरल के साथ उठाया था। इसका अनुसरण फरवरी 2013 में दो वर्षों के बीत जाने के पश्चात तथा बाद में अक्टूबर 2013, जनवरी 2014 तथा जून 2014 में किया गया था। फिर भी, निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जा सका था क्योंकि निदेशक पत्तन, केरल से कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी (दिसंबर 2014)।

इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2014), सहकारी समिति रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, सं.शा.क्षे.ल. प्रशासन ने उत्तर दिया (जनवरी 2015) कि विलम्ब सांविधिक आवश्यकताओं तथा केरल सरकार से सहयोग प्राप्त करने में विलम्ब के कारण था। ल.स.वि.सं. ने जनवरी 2015 अर्थात् पाँच वर्षों से अधिक के पश्चात सं.शा.क्षे. के खाते में ₹27 लाख की आर्थिक सहायता को वापिस किया था। आगे यह उत्तर दिया गया था (जून 2015) कि आर्थिक सहायता का निर्गम इस प्रत्याशा पर आधारित था कि चूंकि ल.स.वि.सं. के गोदाम/कार्यालय परिसर 1970 से प्रस्तावित स्थल पर पहले से ही कार्य कर रहे थे जिसके लिए केरल द्वारा उस समय अनुमति प्रदान की गई थी जब ल.स.वि.सं. की स्थापना की गई थी, इसलिए नवीन अनुमति की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती।

गृह मंत्रालय (अप्रैल 2015) ने लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत करने के लिए प्रशासक, सं.शा.क्षे.ल. को भी ड्राफ्ट पैराग्राफ की एक प्रति समर्थित की थी।

रजिस्ट्रार के उत्तर पर लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया था:

- ♦ गोदाम/कार्यालय के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता को बोर्ड के प्रस्ताव तथा ल.स.वि.सं. द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय संस्वीकृति (दिसंबर 2010) प्रदान किए जाने से भी पूर्व जनवरी 2009 से अगस्त 2010 के बीच जारी किया गया था। बाद में, प्रशासनिक स्वीकृति गोदाम/कार्यालय की स्थापना करने के पहले के प्रस्ताव के स्थान पर चार गोदामों के निर्माण हेतु प्रदान की गई थी।

- ♦ यद्यपि कार्यकारी अभियन्ता ल.लो.नि.वि. तथा ल.स.वि.सं. प्राधिकारियों ने पत्तन निदेशक, केरल की अनुमति हेतु आवेदन किया था फिर भी ल.स.वि.स. द्वारा निधियों के उपयोग को सुनिश्चित करने तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 महीनों के भीतर उपयोग प्रमाणपत्र को प्राप्त करने, जो संस्वीकृति के अनुसार अपेक्षित था, हेतु प्रशासन द्वारा कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, संस्वीकृति आदेश ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संस्वीकृत राशि के अप्रयुक्त भाग, यदि कोई हो, का सरकारी खाते में वापसी का अनुबद्ध किया फिर भी प्रशासन अनुपालना को सुनिश्चित करने में विफल रहा जिसका परिणाम चार वर्षों से अधिक के लिए ₹27 लाख की निधि को अवरोधन में हुआ। यह केवल दिसम्बर 2014 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात किया गया था, जो ल.स.वि.सं. ने प्रशासन को ₹27 लाख वापस किए थे (जनवरी 2015)।